लखनऊ

रविवार 22 फरवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 183

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"सफलता बहानों से नहीं, अपनी कमज़ोरियों को जीत में बदलने की हिम्मत से मिलती है।"

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

संक्षेप

मेहसाणा में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, एक परिवार के 5 लोगों की मौत

मेहसाणा। गुजरात के मेहसाणा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है ।जानकारी के मुताबिक, एक परिवार राजस्थान में शादी में शामिल होने के बाद ईको कार से अहमदाबाद के रामोल वापस लौट रहा था। इस दौरान ऊंझा के उनावा के पास कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा होते ही मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा होते ही मौके पर भीड़ लग गई। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य शुरू किया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में पिता-पुत्र, एक महिला और एक बच्चे सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई है। जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। सड़क हादसे में रामलाल कुमावत, कोमल कुमावत, कैलाश कुमावत, एक बच्चा और एक वृद्ध महिला की मौत हुई है। उनावा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

पीएफआई के सदस्य की जमानत याचिका खारिज, एनआईए ने लगाए हथियार प्रशिक्षण और कट्टरपंथ के आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के शिक्षा विंग के राष्ट्रीय प्रभारी अशरफ उर्फ करमन्ना अशरफ मौलवी को एनआईए की विशेष अदालत से जमानत नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर और ठोस प्रतीत होते हैं, इसलिए इस चरण में उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। एनआईए कोर्ट के जज एमके मोहनदास ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अशरफ इस मामले में दूसरे आरोपी हैं, जो पीएफआई की कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़ा है। वह पालक्काड में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में भी आरोपी बताए गए हैं। जमानत का विरोध करते हुए एनआईए ने अदालत में कहा कि अशरफ ने कोच्चि के पेरियार वैली और तिरुवनंतपुरम के एक संस्थान में पीएफआई कैडरों के लिए हथियारों का प्रशिक्षण आयोजित कराया था। एजेंसी के मुताबिक, यह प्रशिक्षण कथित रूप से आतंकी गतिविधियों की तैयारी के लिए दिया जा रहा था। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कुछ गवाहों ने बयान दिया है कि अशरफ ने हथियार प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया और संगठन के सदस्यों को उकसाने वाले भाषण दिए। एनआईए के अनुसार, उनके घर से बरामद पेन ड्राइव में ISIS से जुड़े वीडियो, तस्वीरें और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली, साथ ही हथियार रखने और कुछ संगठनों के नेताओं की सूची से जुड़े नोट्स भी पाए गए। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि वह आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या की साजिश से जुड़े थे। तलाशी के दौरान एक सह-आरोपी के घर से तलवारें और एक कुल्हाड़ी बरामद होने की बात भी अदालत में बताई गई।

भारत-ब्राजील में क्रिटिकल मिनरल्स समझौता: प्रधानमंत्री मोदी बोले- 5 साल में 20 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का शनिवार को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। दोनों लीडर्स के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक शुरू हो गई है। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते (ट्रेड डील) को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स, डिफेंस, एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस है।

लूला प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत आए हैं। वे 18-22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं। भारत-ब्राजील संबंधों पर लुला ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ 15 अरब डॉलर है, जिसे 30-40 अरब तक बढ़ाना चाहिए। वे 260 ब्राजीलियाई व्यवसायियों के साथ आए हैं ताकि अंतरिक्ष, रक्षा, फार्मा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी हो। एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर भारत में प्लांट खोलेगी। दोनों देश ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और उदाहरण पेश कर सकते हैं। लुला ने यह बात शुक्रवार को इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कही।

चीन की निर्भरता कम करने की तैयारी में भारत-ब्राजील

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की निर्भरता कम करने, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने पर केंद्रित है।

यह समझौता दोनों देशों को कच्चे माल के निर्यातक से आगे बढ़ाकर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और रिसाइक्लिंग में भागीदार बनाने पर जोर देता है।

खनन, प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग: क्रिटिकल मिनरल्स (जैसे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट) और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) पर फोकस।

सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन: चीन पर निर्भरता कम करना, खासकर EV बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी और हाई-टेक इंडस्ट्री के लिए।

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: भारत की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता ब्राजील के संसाधनों के साथ जोड़ी जाएगी।

इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर्स: भारतीय कंपनियां (जैसे KABIL - Khanij Bidesh India Ltd) ब्राजील में निवेश कर सकती हैं, जबकि ब्राजील भारतीय टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस चाहता है।

ग्रीन ट्रांजिशन सपोर्ट: क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और AI से जुड़े टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मिनरल्स की सुरक्षित आपूर्ति।

भारत में छठी बार आकर खुशी हो रही: ब्राजीली राष्ट्रपति

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा, 'मेरे प्रिय मित्र मोदी, इस देश में छठी बार आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और ब्राजील की यह मुलाकात बेहद खास है। हम सिर्फ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें ही नहीं हैं, बल्कि यह एक डिजिटल शक्ति और एक नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति की मुलाकात है।' उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों ही विविधताओं से भरे बड़े देश हैं, सांस्कृतिक उद्योग के बड़े केंद्र हैं और हम दोनों शांति का समर्थन करते हैं।

क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ

भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत और ब्राजील के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यह दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे और रणनीतिक समझ का अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस फायदे वाली साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। मोदी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में सहयोग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं।

सुधांशु त्रिवेदी ने यूथ कांग्रेस को बताया 'लश्कर-ए-राहुल', बोले- देश कभी माफ नहीं करेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 'लश्कर-ए-राहुल' के झंडाबरदार भारत की इज्जत को तार-तार करने में लगे हुए हैं। इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी।

सुधांशु त्रिवेदी ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, ये सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कहकर छोड़ा नहीं जा सकता।' उन्होंने आगे कहा, 'ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी।'

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ते-तोड़ते कांग्रेस पार्टी आज उस स्थिति में पहुंच गई है, जहां राजनीति और राष्ट्र के विरोध की सीमा समाप्त होती है।

यूथ कांग्रेस को बताया 'लश्कर ए राहुल'

यूथ कांग्रेस को 'लश्कर-ए-राहुल' बताते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'अभी तक राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब 'लश्कर-ए-राहुल' के सिपाही भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की आधुनिकतम तकनीक एआई में भारत अग्रिम भूमिका में दिखाई पड़ रहा है, तो कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है।

देश में बड़े आतंकी हमले का हाई अलर्ट, लाल किला और प्रसिद्ध मंदिर लश्कर के निशाने पर, खुफिया एजेंसियों ने दी चेतावनी

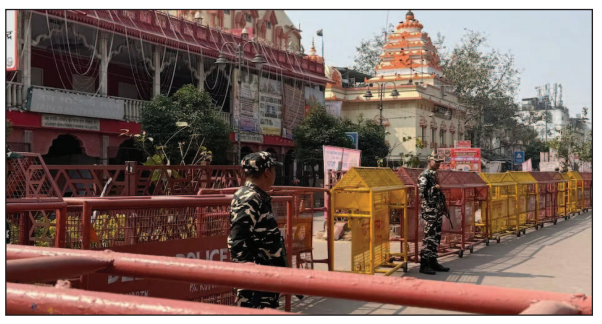

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत को एक बार फिर दहलाने के लिए सरहद पार से नापाक साजिशें रची जा रही हैं। देश की राजधानी समेत कई प्रमुख धार्मिक नगरियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बेहद गंभीर अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभागों को मिले पुख्ता इनपुट्स इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (रुद्रज्ज) खून-खराबे की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस बार आतंकियों के सीधे निशाने पर देश की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ-साथ हिंदुओं के प्रमुख आस्था केंद्र हैं, ताकि देश का माहौल बिगाड़ा जा सके।

ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों पर मंडरा रहा खतरा

खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस आतंकी संगठन का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले इलाकों और पवित्र धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर देश के सांप्रदायिक सौहार्द को गहरी चोट पहुंचाना है। आतंकवादी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के आसपास के क्षेत्रों और घनी आबादी वाले चांदनी चौक इलाके में मौजूद मंदिरों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (ड्रुश्वष्ठ) के जरिए निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। राजधानी के अलावा उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भी आतंकियों के हिट लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इन सभी जगहों की सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई है।

इस्लामाबाद ब्लास्ट का बदला लेने की साजिश

अलर्ट में इस बात का भी सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि भारत में दहशत फैलाने की यह साजिश असल में बदले की आग का नतीजा है। बताया जा रहा है कि बीते 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक मस्जिद में हुए जोरदार धमाके के बाद से ही लश्कर के ऑपरेटिव पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इसी घटना का बदला लेने के लिए वे भारत के किसी बड़े और संवेदनशील हिस्से में बड़ा आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहे हैं, ताकि आम जनता के बीच खौफ का माहौल पैदा किया जा सके।

देश भर में धड़ल्ले से चल रहीं 32 फर्जी यूनिवर्सिटी, यूजीसी ने जारी की लिस्ट, दिल्ली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्च शिक्षा हासिल कर सुनहरे भविष्य का सपना देखने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। अगर आप किसी भी नए संस्थान में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं, तो जरा सतर्क हो जाइए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर में शिक्षा के नाम पर दुकान चला रहे 32 फर्जी विश्वविद्यालयों का भंडाफोड़ किया है। आयोग ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए साफ किया है कि इन अवैध संस्थानों से बांटी जा रही कोई भी डिग्री न तो किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए मान्य होगी और न ही इसके आधार पर आगे की पढ़ाई की जा सकेगी। यूजीसी के ताजा आंकड़ों ने उच्च शिक्षा व्यवस्था की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चिंताजनक बात यह है कि पिछले महज दो सालों के भीतर ही इन गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या 20 से उछलकर 32 तक पहुंच गई है। इस काली सूची में देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां अकेले 12 फर्जी यूनिवर्सिटी सक्रिय पाई गई हैं। इसके अलावा, इस बार हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के नाम भी इस सूची में जुड़ गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी शिक्षा के नाम पर यह गोरखधंधा बदस्तूर जारी है।

बेंगलुरु के संस्थान पर विशेष अलर्ट, लुभावने वादों से बिछाते हैं जाल

फर्जीवाड़ा करने वाले ये संस्थान छात्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए बेहद शातिर हथकंडे अपनाते हैं। यूजीसी ने बेंगलुरु में संचालित हो रहे ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी को लेकर विशेष रूप से एक अलग चेतावनी जारी की है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे संस्थान अक्सर कम फीस, बिना ज्यादा मेहनत के जल्दी डिग्री देने और आसान पढ़ाई का लालच देकर भोले-भाले छात्रों को बरगलाते हैं। कई बार ये संस्थान खुद को किसी बड़े विदेशी विश्वविद्यालय की शाखा बताकर भी गुमराह करते हैं, जबकि असलियत में इनके पास न तो पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक होते हैं।

'31 मार्च तक देश से खत्म होगा नक्सलवाद'

असम में पहली बार हुई सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड में बोले शाह

दिसपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस परेड का असम में पहली बार आयोजन होना पूरे पूर्वोत्तर के लिए गर्व का क्षण है। गुवाहाटी में आयोजित परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 86 साल के इतिहास में पहली बार सीआरपीएफ की रेजिंग डे परेड पूर्वोत्तर में हो रही है, जो क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है। शाह ने बताया कि 2019 में निर्णय लिया गया था कि यह वार्षिक परेड देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित की जाएगी।

परेड को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां पत्थरबाजी की घटनाओं की संख्या घटकर शून्य हो गई है, इसके अलावा मणिपुर में जातीय हिंसा से निपटने और केवल तीन वर्षों में माओवादियों की कमर तोड़ने के लिए भी बल को तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं सीआरपीएफ पर भरोसा कर सकता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम 31 मार्च तक देश से नक्सल समस्या का सफाया कर देंगे।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 की शुरुआत

इससे पहले गृह मंत्री ने कछार जिले के कटिगरा स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के नतनपुर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत देश के 17 राज्यों के 334 ब्लॉकों और करीब 1,954 गांवों के साथ-साथ असम के 140 सीमावर्ती गांवों में विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

श्रीनगर में बड़ा हादसा, नहर में गिरा सीआरपीएफ का बुलेटप्रूफ वाहन, 9 जवान घायल

जम्मू। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक बुलेटप्रूफ वाहन हादसे का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। इस हादसे में वाहन में सवार 9 जवानों के घायल होने की जानकारी है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जवानों को नहर से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है।

बताया जा रहा है कि शनिवार को अहमद नगर रोड पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का बुलेटप्रूफ बंकर वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। घटना के समय बुलेटप्रूफ वाहन में 9 जवान सवार थे। सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और सुरक्षाबलों की मदद से बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और सभी घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है।

डगपोरा-उमरहैर रोड पर हुआ हादसा

स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि श्रीनगर के बाहरी इलाके अहमदनगर इलाके में डगपोरा-उमरहैर रोड पर यह हादसा हुआ है। ड्राइवर का वाहन पर कंट्रोल खोने के कारण हादसा हुआ है। घायल जवानों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। नहर में गिरे वाहन को क्रेन के सहारे बाहर निकाल लिया गया है। अधिकारी का कहना है कि स्थानीय लोगों की मदद से घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी की हालत ठीक बताई जा रही है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कई यूजर्स ने घटना की वीडियो शेयर कर हादसे पर भी सवाल उठाए हैं। वीडियो में बुलेटप्रूफ वाहन नहर में गिरा दिखाई जा रही है। जबकि आसपास स्थानीय पुलिस, सेना और लोगों की भीड़ दिख रही है। एक वीडियो में नहर से वाहन को निकाला जा रहा है। जबकि एक वीडियो अधिकारी घटना को लेकर बात कर रहे थे। स्थानीय लोगों से भी घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है।

गोवा से समुद्री सुरक्षा का संदेश : हिंद महासागर पर भारत की कूटनीतिक पहल, एक साथ आए 14 देशों के नौसैनिक प्रमुख

पणजी। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती समुद्री चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर नेतृत्व की भूमिका निभाई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गोवा में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में हिंद महासागर से जुड़े 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन का मकसद समुद्र में बढ़ते खतरों से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। इस सम्मेलन में ड्रग तस्करी, अवैध और अनियमित मछली पकड़ने जैसी गंभीर समस्याओं पर चर्चा हुई। नौसेना प्रमुख ने कहा कि ये चुनौतियां सिर्फ किसी एक देश की नहीं हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करती हैं। सम्मेलन का विषय "हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियां और बदलते खतरों से निपटने के प्रयास" रखा गया है। इस मौके पर दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल समीर सक्सेना और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश भी मौजूद रहे।

14 देशों की भागीदारी

इस कॉन्क्लेव में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कोमोरोस, मलेशिया, केन्या, सिंगापुर, मेडागास्कर, थाईलैंड, म्यांमार, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इन देशों ने समुद्री सुरक्षा से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सभी देशों ने माना कि समुद्र में अपराध अब संगठित और तकनीकी रूप से मजबूत हो चुके हैं, जिनसे निपटने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है।

वाराणसी में पपुलिस ने सपाइयों को दालमंडी में जाने से रोका, पुलिस अभिरक्षा में पार्टी जलिाध्यक्ष

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

वाराणसी। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रस्तावति दालमंडी क्षेत्र का दौरा करने की जानकारी सामने आने के बाद पुलसि ने सभी पार्टी पदाधकिारयिों को पुलसि अभरिक्षा में सुबह से ही ले लयिा गया। इस दौरान सपा नेता समद अंसारी को दालमंडी जाने से रोका गया। उनको दालमंडी जाने के दौरान प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यह घटना उस समय हुई जब वे दालमंडी के पीड़ितों, भवन स्वामियों, दुकानदारों एवं व्यापारियों से मिलने के लिए जा रहे थे।

वहीं दोपहर में दालमंडी में पीड़ित परिवार से मिलने जा रही सपा की पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव को पुलिस ने रोका और वहां से उनको हटा दयिा। बताया कि सपा की पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव दालमंडी पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थीं, तभी चौक पुलिस ने उन्हें दालमंडी मोड़ पर रोक लिया और थाने ले आई।

जानकारी के अनुसार प्रशासन ने सुबह सात बजे से ही सपा के कई कार्यकर्ताओं को उनके घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट किया। दालमंडी में स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने वहां जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सपा के पदाधिकारियों के घरों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अर्दली बाजार स्थित सपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुजीत यादव को लक्कड़ पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है।

इस बीच, सपा के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद उत्तर प्रदेश, लालबिहारी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 21 फरवरी 2026 को दोपहर 2:00 बजे वाराणसी के सर्किट हाउस से दालमंडी के पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचेगा। यह प्रतिनिधि मंडल दालमंडी में व्यापारियों और दुकानदारों की समस्याओं को सुनकर उनकी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा।

समद अंसारी ने कहा कि प्रशासन का यह कदम लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी समस्याओं को उठाने का कार्य करती रहेगी।

सपा के कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि यह सरकार की तानाशाही का एक उदाहरण है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें दालमंडी जाने की अनुमति दी जाए ताकि वे वहां के व्यापारियों और दुकानदारों की समस्याओं को समझ सकें।

इस घटनाक्रम ने जलि में राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। सपा के नेता और कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे दालमंडी के पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी आवाज को उठाएंगे। इस प्रकार, दालमंडी का यह मुद्दा न केवल स्थानीय व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सपा के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सपा के नेता इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।

शिकायतों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित करें अधिकारी : डीएम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। तहसील लम्भुआ में आयोजित 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में जिलाधिकारी कुमार हर्ष एवं पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान जमीनी विवाद से जुड़े मामलों पर विशेष जोर दिया गया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर करें, ताकि शिकायतकर्ताओं को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें त्वरित व न्यायपूर्ण समाधान मिल सके। शासन के नि र्दे शा नु सा र प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को जिले की सभी तहसीलों में उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में 21 फरवरी 2026 को लम्भुआ तहसील में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एसपी चारू निगम ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

'बहती हवा सा था वो . . .ओम शांति ओम', कानपुर में सिंगर शान के गानों पर झूमे लोग ; 2 घंटे दी परफॉर्मेंस

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कानपुर।गुलाबी सर्द शाम में कलरफुल लेजर लाइट से रोशन सीएसए कृषि विश्वविद्यालय का ग्राउंड। पूरे परिसर में गूंजता मधुर संगीत। मौका था गार्डेनिया पब्लिक स्कूल, राधापुरम गूबा गार्डेन के वार्षिकोत्सव जेनेसिस के अंतिम दिन शुक्रवार को बालीवुड सिंग शान की लाइव परफार्मेंस आयोजन का।

शाम सात बजे के करीब जैसे की शान ने मंच पर जोशीले अंदाज और सुरीली आवाज में एक के बाद एक बालीवुड गीत गाने शुरू किए तो उनकी मधुर आवाज का ऐसा जादू चला कि प्रांगण में मौजूद सभी के दिलों को छू लिया। शाम को सुरों की ऐसी बारिश हुई कि प्रांगण में मौजूद अतिथि, छात्र-छात्राएं, शिक्षिकाएं और अभिभावक खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। सिंगर शान ने मंच पर मैं हूं डान... गीत के साथ धमाकेदार एंट्री ली। इसके बाद हम जो चलने लगे, चलने लगे हैं ये रास्ते..., बम बम भोले, मस्ती में डोले..., जिसे ढूंढता हूं मैं हर गली, वो लड़की है कहां..., ये लड़की क्यूं न जाने क्यूं, लड़कों सी नहीं होती..., चांद सिफारिश जो करता हमारी..., बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो..., ओ हम दम सुनियो रे..., ओम शांति ओम..., दस बहाने करके ले गया दिल..., जैसे अपने कई हिट नंबर्स एक के बाद लगातार प्रस्तुत किए। शान ने बीच-बीच में विद्यार्थियों से संवाद करके कानपुर से अपने को जोड़ा। पार्श्व गायक शान के गाए गीतों पर दर्शक जमकर झूमे। दो घंटे तक चली लाइव परफार्मेंस के अंत में गायक शान ने बच्चों को नशे के सेवन से दूर रहने का आह्वान किया।

यहां डीआइओएस डा. संतोष कुमार राय, बीएसए सुरजीत कुमार सिंह, स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमन द्विवेदी, फाउंडर अनिल द्विवेदी, डायरेक्टर नीलम द्विवेदी, चीफ डायरेक्टर सौरभ द्विवेदी सहित स्टाफ सदस्य, अभिभावक व विद्यार्थी मौजूद रहे।

हमलावर वनरोज का वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

कुड़वार सुल्तानपुर। बीते पखवारे भर से ग्रामीणों पर हमलावर हुए वनरोज को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान के तहत पकड़कर जंगल में छोड़वा दिया। मामला स्थानीय थाना क्षेत्र के कोटिया गांव से जुड़ा है।06 माह पूर्व घायल अवस्था में वनरोज गांव में पहुंचा था।जिसे गांव निवासी ओझाउल कमर ने इलाज करा दिया जिसके बाद वनरोज उनके परिवार के साथ घुल मिल गया और गांव में ही रहने लगा था।बीते 15 दिनों से वनरोज हमलावर हो गया।वनरोज के हमले से कांति देवी, एहसान, जाहिद आदि घायल हो गए।वनरोज के हमलावर होने की सूचना ग्रामीणों ने वनविभाग को दी।सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू करके पकड़ लिया।और दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।वन विभाग की टीम में बीट इंचार्ज सौरभ यादव,माली संतराज,चौकीदार विश्राम, मेराज अहमद, इलियास, मोईद, जाहिद, गुफरान आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे।

इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा 1 .28 लाख परीक्षार्थियों ने छोड़ी, पांच साल्वरों के विरुद्ध एफआईआर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की शुक्रवार को हुई परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 51,22,005 परीक्षार्थियों में से 2,98,959 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। इसमें 1,28,769 वह परीक्षार्थी भी हैं, दो इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पंजीकृत थे, लेकिन अनुपस्थित रहे।

UP Board Exam 2026 बोर्ड की तीसरे दिन की परीक्षा में पांच साल्वरों को दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसके अलावा हाईस्कूल में दो तथा इंटरमीडिएट में एक परीक्षार्थी को नकल करते पकड़ा गया है। शुक्रवार को प्रथम पाली में हाईस्कूल के सामाजिक विज्ञान तथा इंटरमीडिएट के विषय कृषि शस्य विज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1) एवं कृषि शस्य विज्ञान षष्टम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2) की परीक्षा कराई गई। इसके लिए पंजीकृत 27,67,087 में से 1,70,190 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी। इसी तरह दूसरी पाली में इंटरमीडिएट अंग्रेजी की परीक्षा हुई, जिसके लिए 23,54,918 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।

कहां पकड़े गए साल्वर

UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह के अनुसार प्रथम पाली में गोरखपुर और प्रतापगढ़ तथा दूसरी पाली में झांसी, कन्नौज एवं एटा में एक-एक साल्वरों को पकड़ा गया। प्रथम पाली में फिरोजाबाद व मैनपुरी में एक-एक तथा द्वितीय पाली में कन्नौज में एक परीक्षार्थी को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़कर कार्रवाई की गई है। इस तरह अब तक कुल सात परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए हैं, जबकि पकड़े गए साल्वरों की संख्या 11 हो गई है। साल्वरों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई की गई है।

राहुल गांधी का पुतला फूंक भाजयुमो ने किया प्रदर्शन, AI समिट पर जताया विरोध

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिले में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित अभद्र प्रदर्शन और देश की छवि धूमिल करने के विरोध में किया गया। भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सुल्तानपुर में कलेक्ट्रेट गेट के सामने नगर कोतवाल सहित कई पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह प्रदर्शन हुआ। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह के नेतृत्व और प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह की अगुवाई में सैकड़ों पदाधिकारियों ने राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान 'गली-गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है' और 'राहुल गांधी मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस घटना के पीछे के मुख्य सूत्रधारों की पहचान की जाए और भविष्य में ऐसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश की स्थिति खराब थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दस सालों में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को यह बात अखर रही है कि प्रधानमंत्री कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में चार दिन पहले हुई AI समिट का भी जिक्र किया, जिसमें दुनिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ और एमडी शामिल हुए थे।

गुटखा पान मसाला की कालाबाजारी जोरों पर

सुल्तानपुर। जनपद में इन दिनों गुटखा पान मसाला मूल्य से अधिक दामों पर बड़े व्यवसाई बेच रहे हैं। जिससे छोटे दुकानदारों को अधिक मूल्य पर ग्राहकों को सिग्नेचर, राज श्री, कमला पसंद गुटखा मसाला बेचा जा रहा है।

नाम न छापने की शर्त पर फुटकर व्यवसायियों ने बताया कि एक पैकेट एक माह पहले कमला पसंद (39 पाउच) 165 रुपए में मिलता था जो अब 250 रुपए में, राज श्री एक पैकेट एक माह पहले (30 पाउच) 125 रुपए में मिलता था जो अब 185 रुपए में, सिग्नेचर गुटखा एक पैकेट एक माह पहले (54 पाउच) 220 रुपए में मिलता था जो अब 320 रुपए में बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जनपद के होलसेलर बड़े व्यवसाइ मनमाने तरीके से इन गुटखों के रेट में बढ़ोतरी की है जिससे गुटखा खाने वाले की जेब ढीली हो रही है। जनपद में हो रही इस तरह की कालाबाजारी की जानकारी प्रशासन को या तो नहीं है या फिर इस काला बाजारी की मौन स्वीकृति दी गई है।

'मैं बिजली चोर नहीं साहब...' 20 साल तक चली कानूनी लड़ाई, कैसे मिटा चोरी का 'दाग'?

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बिजली चोरी के गंभीर आरोप में फंसे एक उपभोक्ता को करीब दो दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने पूरी तरह से बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) एवं अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी शर्मा की अदालत ने विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित न कर पाने के कारण देवेश कुमार सागर को दोषमुक्त करार दिया। अदालत के फैसले से उपभोक्ता और उनके परिवार ने बड़ी राहत महसूस की।

मामला इस्लामगंज, थाना दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले देवेश कुमार से जुड़ा है। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने 27 दिसंबर 2005 को उनके घर पर जांच कर एलटी लाइन में कट दिखाते हुए बिजली चोरी का आरोप लगाया था। विभाग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान विभाग अपने दावों को साबित नहीं कर पाया।

बिजली चोरी के मामले कोर्ट ने किया बरी

अदालत में विभाग ने दावा किया कि मौके से 11 मीटर केबल बरामद की गई थी। लेकिन जांच के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि चेकिंग रिपोर्ट किसने तैयार की थी। कई सवालों के जवाब विभाग नहीं दे सका, और कथित जब्त केबल भी अदालत में प्रस्तुत नहीं की गई। अभियोजन पक्ष के कई गवाह लगातार नहीं आए, जबकि उनके खिलाफ जमानती और गैर-जमानती वारंट भी जारी हो चुके थे। अंततः न्यायालय ने साक्ष्यों की कमी को देखते हुए उपभोक्ता को बरी कर दिया।

समझौता करने से किया था इनकार

वर्ष 2016 में देवेश कुमार से कहा गया था कि लगभग 5056 हजार रुपये देकर मामला सुलझाया जा सकता है। विभाग ने कई बार समझौते के प्रस्ताव दिए और जुर्माने को कम करने का प्रलोभन भी दिया, लेकिन देवेश कुमार ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब उन्होंने चोरी नहीं की है, तो आरोप क्यों मानें। उन्होंने बताया कि 20 साल की कानूनी लड़ाई में करीब 4045 हजार रुपये खर्च हुए और कई बार नौकरी से छुट्टी लेकर अदालत के चक्कर काटने पड़े, लेकिन अब उन्हें संतोष है कि सच की जीत हुई।

पीड़ित ने क्या कहा?

बिजली चोरी के आरोप के चलते लंबे समय तक उन्हें घरेलू कनेक्शन नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने अपने घर की बिजली पत्नी के नाम पर लगे कॉमर्शियल मीटर से ही उपयोग की। बिल कम होने के बावजूद उन्होंने समझौते को ठुकरा कर कानूनी लड़ाई जारी रखने को प्राथमिकता दी। देवेश कुमार का कहना है कि विजिलेंस टीम ने गलत तरीके से बिजली चोरी का मामला दर्ज किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब चोरी नहीं की है तो सुलह का कोई सवाल ही नहीं उठता। लगभग 20 साल की लंबी लड़ाई में अदालत ने अंततः न्याय प्रदान कर उपभोक्ता को राहत दी, यह साबित करते हुए कि न्याय चाहे देर से मिले, लेकिन जरूर मिलता है।

यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, खरीदी जाएगी 16 गांवों की 740 एकड़ जमीन, 1204 करोड़ रुपये की मंजूरी

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरकार बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। सरकार का प्लान है कि यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का जाए। इसके लिए जमीन खरीद के लिए सरकार ने बजट भी पास कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) को 1204 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर दिया है।

नोएडा में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार योजना बनाकर तेजी से काम कर रही है। सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे को बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए यीडा क्षेत्र के 16 गांवों की करीब 740 एकड़ जमीन खरीदने पर जोर दिया जा रहा है। जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पर काम तेज हो जाएगा।

राज्य सरकार ने जमीन खरीदने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) को 1204 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यूपी सरकार के संयुक्त सचिव निर्मष कुमार शुक्ल ने यीडा के सीईओ को इससे संबंधित पत्र भेजा है, जिसे 17 फरवरी को जारी कर दिया गया था।

यूपीडा करेगा निर्माण

गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य करने की जिम्मेदारी यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दी गई है। लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र से शुरू होगा और यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर यानी सेक्टर-21 फिल्म सिटी के पास आकर जुड़ेगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे का करीब 20 किलोमीटर का हिस्सा यीडा क्षेत्र में है। इसमें से 9 किलोमीटर के भाग में एलिवेटेड निर्माण भी शामिल है। इसके असावा, स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा।

16 गांवों से होगी जमीन की खरीद

गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 16 गांवों की लगभग 740 एकड़ जमीन की खरीदी जाएगी, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार जमीन खरीदने के लिए 1204 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जेवर के मेहंदीपुर बांगर, भाईपुर ब्रह्मनान, रबुपूरा, भुन्नातगा, म्याना, फाजिलपुर और कल्लूपुरा में अथॉरिटी ने सर्वेक्षण के बाद जमीन खरीद की तैयारी की है।

सपना सच होने जैसा है मेरठ से दिल्ली का सफर एक घंटे में पूरा होना

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। 2019 के पहले अगर कोई यह कहता था कि मेरठ से दिल्ली का सफर एक घंटे के अंदर पूरा होगा तो वह किसी दिवा स्वप्न जैसे लगता था। दूरी तब भी लगभग 70 किलोमीटर ही थी, लेकिन तब दिल्ली बहुत दूर लगती थी। मोदीनगर, मुरादनगर और राजनगर एक्सटेंशन को पार करना मेरठ वासियों के लिए किसी दुःस्वप्न जैसे होता था। एकाध बार तो ये भी हुआ कि शाम से सफर शुरू हुआ और जाम ऐसा लगा कि मेरठ पहुंचने में भोर हो गई।

2010 के आसपास रैपिड रेल को लेकर कवायद शुरू हुई थी। अखबारों में खबरें आनी शुरू हुईं लेकिन किसी को यकीन नहीं होता था कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि 40 से 50 मिनट में दिल्ली तक का सफर पूरा हो जाएगा। 2011 की बात है। मैं जीटी एक्सप्रेस से चेन्नई से लौट रहा था। रास्ते में पत्नी के असमय प्रसव पीड़ा की सूचना मिली।

ट्रेन सुबह छह बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंच गई थी। मेरठ पहुंचने में मुझे पूरे पांच घंटे लग गए थे। इस दौरान खुद पर खीझने और व्यवस्था पर झुंझलाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। जब तक पहुंचा मिसकैरिज हो चुका था। शुक्रवार को जब सराय काले खां से नमो भारत ट्रेन चली और 39 मिनट में बेगमपुल पहुंची तो वह पूरा वाकया फिर से ताजा हो गया।

यह अकेली नहीं, ऐसी अनगिनत कहानियां होंगी जो लोगों को सालती होंगी। काश! दिल्ली के नजदीक प्रमुख शहरों में शामिल मेरठ तब सरकारों की प्राथमिकता में रहा होता। पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और अब रैपिड रेल प्रोजेक्ट का पूरा होना मेरठवासियों के लिए एक सपने के साकार होने जैसा है।

खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी के तमाम खूबसूरत लम्हे मोदीनगर के जाम में जाया हुए हैं। खैर, समय ने अब पूरा शीर्षासन कर लिया है। आने वाली पीढ़ी को आज के 10 साल बाद अगर कोई यह बताएगा कि कभी मेरठ से दिल्ली पहुंचने में चार से पांच घंटे लगते थे, तो उनके लिए यह कल्पना भी आश्चर्य से कम भाव नहीं लाएगी।

पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर यूनिट का किया शिलान्यास, बोले- अब भारत में क्रांति की शुरुआत

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की।

'सेमीकंडक्टर सप्लाई न होने से कई कंपनियां बंद हुईं'

यमुना सिटी में सेमीकंडक्टर यूनिट की वर्चुअली तरीके से आधारशिला रखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर यूनिट लगने से भारत में तकनीकी क्रांति शुरुआत होने जा रही है। कोविड काल में सेमीकंडक्टर सप्लाई न होने से कई कंपनियां बंद हो गई थी। उस समय भारत ने आपदा में अवसर को तलाशा था और अपनी सेमी कंडक्टर यूनिट लगाने का निर्णय लिया था। जो अब पूरा होने जा रहा है।

सीएम योगी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बताया

सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री का हृदय से अभिनंदन किया और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनका स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को उभरती हुई तकनीक के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने पिछले चार दिनों से चल रहे भारत मंडपम में इम्पैक्ट समिट का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस समिट में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष भागीदारी की।

दुनिया के 110 से अधिक देशों की सहभागिता भी इस सम्मेलन में रही। इम्पैक्ट समिट के माध्यम से भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का विजन दिया गया है। इसका उद्देश्य मानवता के जीवन को और भी सरल तथा सुगम बनाना है। सीएम योगी ने इस दूरदर्शी विजन के लिए स्वयं और पूरे प्रदेश की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देश समग्र विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत उभरती हुई तकनीक का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह देश की प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इम्पैक्ट समिट का वैश्विक प्रभाव

भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट को मुख्यमंत्री ने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस सम्मेलन में 10 लाख से अधिक लोगों ने सीधे भाग लेने का अनुमान जताया। दुनिया के 110 से अधिक देशों ने भी इसमें अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। समिट ने भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का एक स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया। इसका लक्ष्य मानवता के जीवन को सरल और सुगम बनाना है, जिसके लिए सीएम योगी ने आभार व्यक्त किया।

किसानों को सीएम योगी का तोहफा, 2 .51 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजे 460 करोड़ रुपये

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ढाई लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में 460 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति राशि दी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा, राज्य में आपदा मैनेजमेंट में सबसे पहले 'आपदा मित्र' ही हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासकर 25 जिलों में NCC, NSS, NYKS, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स समेत 29,772 युवा वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है। उनके साथ मिलकर हमने आपदा मित्र मैनेजमेंट से जुड़े सभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। सरकार बदली तो हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की।

फार्माफ्यूचरएक्स–2026 में लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा को द्वितीय स्थान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 21-22 फरवरी 2026 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन "डिजिटल हेल्थ, एआई एवं स्मार्ट फार्मा फॉर विकसित उत्तर प्रदेश" (फार्माफ्यूचरएक्स-2026) के अंतर्गत आयोजित पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता में लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा दीपांशी श्रीवास्तव ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है।लखनऊ विश्वविद्यालय के फार्मास्युटिकल साइंसेज संस्थान की तृतीय वर्ष की छात्रा दीपांशी ने "प्राकृतिक फ्लेवोनॉइड्स बहु-लक्ष्य हृदय संरक्षक एजेंट के रूप में: कैलपेन एवं लिपोप्रोटीन अंतःक्रियाओं पर एआई-संवर्धित आणविक डॉकिंग अध्ययन" विषय पर अपना शोध पोस्टर प्रस्तुत किया। इस शोध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आणविक डॉकिंग तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक फ्लेवोनॉइड्स के हृदय संरक्षण संबंधी गुणों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में हृदय रोगों की रोकथाम के लिए बहु-लक्ष्य उपचार की संभावनाओं को रेखांकित किया गया, जो भविष्य में कार्डियोवैस्कुलर रोगों के उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।इस शोध कार्य में फार्मास्युटिकल साइंसेज संस्थान के फार्माकोग्नोसी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अभिषेक कुमार ने छात्रा का मार्गदर्शन किया। उनके निर्देशन में यह शोध सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। सम्मेलन में देश-विदेश के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने सहभागिता करते हुए डिजिटल स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्मार्ट फार्मा से जुड़े नवीनतम शोध प्रस्तुत किए।कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरिंदर सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं भारत के पूर्व औषधि महानियंत्रक डॉ. जी. एन. सिंह उपस्थित रहे। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति में सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।दीपांशी श्रीवास्तव की इस उपलब्धि पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे विश्वविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। संकाय सदस्यों ने भी छात्रा की सराहना करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और इसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता तथा शोध उत्कृष्टता का प्रमाण बताया।

लखनऊ में 'यूथ हेरिटेज लीडरशिप प्रोग्राम' का आयोजन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय "यूथ हेरिटेज लीडरशिप प्रोग्राम" का आयोजन किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इतिहास संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के महत्व से परिचित कराना और उन्हें विरासत संरक्षण के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करना था।कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को राजधानी लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों ने छतर मंजिल और कैसरबाग स्थित जनरल कोठी का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान इन स्थलों के इतिहास, स्थापत्य शैली और संरक्षण से जुड़े पहलुओं की जानकारी सरल एवं प्रभावी तरीके से दी गई।

मिशन शक्ति 5 .0 के तहत बीकेटी में छात्राओं को किया गया जागरूक, सुरक्षा और अधिकारों की दी गई विस्तृत जानकारी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बीकेटी क्षेत्र के अंतर्गत महिला थाना द्वितीय की टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, कुम्हरावा, बीकेटी में भ्रमण कर छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को सामान्य अपराधों एवं साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें सीईआईआर पोर्टल के उपयोग, यूपी कॉप एप की उपयोगिता तथा आपात स्थितियों में सहायता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों—1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1098 (बाल संरक्षण), 101 (अग्निशमन), 102 और 108 (स्वास्थ्य आपात सेवा), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) तथा 1930 (साइबर हेल्पलाइन)—की जानकारी दी गई। साथ ही महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया।महिला उपनिरीक्षक अनु देवी, महिला उपनिरीक्षक सृष्टि निगम, महिला कांस्टेबल सरिता, रूबी और सीमा कुमारी सहित टीम के अन्य सदस्यों ने छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें आत्मरक्षा, सतर्कता और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में जागरूकता संबंधी पंपलेट्स भी वितरित किए गए।आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए साइबर सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया। छात्राओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और साइबर उत्पीड़न से बचने के व्यावहारिक उपाय बताए गए तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल 1930 पर संपर्क करने की सलाह दी गई।मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ के 54 थानों पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जहां महिलाओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है। थानों पर आने वाली महिलाओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।यह पहल छात्राओं और महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति सजग बनाने तथा पुलिस सहायता तक उनकी पहुंच को सुलभ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिना अनुमति के कॉरिडोर से हटाया गया था महानगर मेट्रो स्टेशन, 22 मेट्रो स्वीकृत थे, 21 का निर्माण हुआ

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1ए (उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर) में स्वीकृत 22 मेट्रो स्टेशन के सापेक्ष 21 का ही निर्माण किया गया था। 22वां महानगर मेट्रो स्टेशन कॉरिडोर से हटा दिया गया था। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी से अनुमति तक नहीं ली गई थी जबकि जहां पर ये स्टेशन बनना था वहां पर दैनिक यात्री क्षमता दूसरे स्थान पर थी।

ये खुलासा शुक्रवार को दोनों सदनों के पटल पर रखी गई लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के निर्मण एवं संचालन की सीएजी रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के तहत 22.88 किमी में 22 स्टेशन बनने थे। डीपीआर से लेकर अन्य सभी दस्तावेजों में 22 स्टेशन बनाए जाने का ही तथ्य था।

स्वीकृति भी थी परियोजना रिपोर्टमें महानगर मेट्रो स्टेशन को वर्ष 2015 में दैनिक यात्री क्षमता के मद्देनजर तीसरा व वर्ष 2020 में दूसरे स्थान पर होना था। सीएजी रिपोर्ट में पाया गया कि महानगर स्टेशन नहीं बनाया गया। ये स्टेशन परियोजना से बाहर किए जाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव केंद्र, राज्य सरकार या संबंधित अथॉरिटी से स्वीकृत लेने संबंधी नहीं मिला। स्पष्ट हुआ कि बिना किसी स्वीकृति के महानगर स्टेशन परियोजना से बाहर कर दिया गया। इससे वहां के यात्रियों को इसकी सुविधा नहीं मिल सकी।

शर्तों का किया गया उल्लंघन

भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति के तहत कई शर्तों का भी पालन नहीं किया गया। शर्तों के मुताबिक जिला शहरी परिवहन निधि की स्थापना, विज्ञापन व पार्किंग नीति तैयार करना और समय समय पर किराया संशोधन करना था। सीएजी रिपोर्ट में सामने आया कि इन शर्तों का पालन नहीं किया गया।

विवादित जमीन पर डिपो का निर्माण

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए 25.80 हे भूमि खरीदी गई थी। इसमें से 1.98 हे जमीन विवादित थी। जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था। विवादित जमीन पर भी डिपो का निर्माण कराया गया। रिपोर्ट कें मुताबिक ये निर्माण वित्तीय नियमों विरुद्ध था।

यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़

मेट्रो के संचालन के लिए अंतरिम गति प्रमाण लिया जाता है। इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए होती है। जिससे पता चलता है कि मेट्रो का सफर कितना सुरक्षित है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पांच वर्ष बाद प्रमाण पत्र का नवीनीकरण ही नहीं कराया गया। इससे पहिये की घिसावट व एडजस्टमेंट की आवश्यकता को पता नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की नई परफॉरमेंस-बेस्ड ग्रेडिंग नीति लागू

लखनऊ। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देशन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई परफॉरमेंस-बेस्ड ग्रेडिंग नीति लागू की है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की इस पहल का उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और युवाओं की रोजगार क्षमता को सशक्त बनाना है।मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शी मूल्यांकन और गुणवत्ता आधारित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

डॉक्टरों के वॉक इन इंटरव्यू में खेल : एक मिनट 40 सेकेंड में हुए इंटरव्यू, अभ्यर्थी ने लगाया गड़बड़ी का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। सीएमओ के अधीन हुए डॉक्टरों के वॉक इन इंटरव्यू में खेल हुआ है। एक से डेढ़ मिनट के अंदर डॉक्टरों का इंटरव्यू लेकर उन्हें चलता कर दिया गया। आरोप है इंटरव्यू कमेटी ने चयन प्रक्रिया में सिर्फ खानापूर्ति किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत डिप्टी सीएम से करने की बात कही है।

मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर खुले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर संविदा पर एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए बीते माह सात जनवरी में सीएमओ ऑफिस में वॉक इन इंटरव्यू हुआ था। 55 पद के सापेक्ष 350 डॉक्टर इंटरव्यू में शामिल हुए थे। इसमें निजी मेडिकल कॉलेज से एक से डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करके एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर भी शामिल हुए थे।

विदेश व निजी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को विभाग के कर्मचारियों ने ईडब्लूएस का प्रमाण पत्र बनवाने की सलाह दी। ईडब्लूएस कोटे के जरिय कई अपात्र लोगों ने नौकरी पा लिया है। वहीं इंटरव्यू की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। जो शाम सात बजे तक चली। आठ घंटे में गणना के अनुसार एक मिनट 40 सेकेंड में डॉक्टरों का इंटरव्यू लेकर खानापूर्ति की गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

अभ्यर्थी बोले सिर्फ खानापूर्ति हुई

एक महिला डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्ता पर बातचीत में बताया कि उनका इंटरव्यू करीब चार मिनट तक कमेटी के जरिये लिया गया था। कमेटी ने कई सवाल भी किए। जिनका उत्तर ही ठीक ढंग से दिया गया। इसके बाद भी उनका चयन नहीं हुआ। हमारे कॉलेज के कई वरिष्ठ डॉक्टरों के इंटरव्यू प्रक्रिया में खानापूर्ति की गई। किसी को एक मिनट तो किसी को डेढ़ मिनट के बाद कक्ष से बाहर कर दिया गया। ऐसे में कमेटी के जरिये इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया में खानापूर्ति हुई है।

अभ्यर्थी को बुलाने व कुर्सी तक बैठने में लग गया 30-40 सेकेंड

अभ्यर्थियों का कहना है इंटरव्यू की प्रक्रिया सीएमओ ऑफिस के तीसरे तल के सभागार में चल रही थी। सभागार कक्ष में महज 80 लोगों के बैठने के इंतजाम है। ऐसे में बाकी अभ्यर्थी हाल के बाहर खड़े इंतजार कर थे। नंबर आने से लेकर कुर्सी तक बैठने में अभ्यर्थी को तीस से चालीस सेकेंड का समय लग रहा था। ऐसे में कई अभ्यर्थी से इंटरव्यू में सिर्फ एक दो प्रश्न पूछकर उन्हें बाहर कर दिया गया।

सीएमओ बोले-पूरी निष्पक्षता से इंटरव्यू लिया

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि कमेटी के जरिये पूरी निष्पक्षता से इंटरव्यू लिया है। जो भी अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। अभ्यर्थी शिकायत करते हैं तो मामले की जांच कराई जाएगी।

यू समझे गणना

एक घंटे में 60 मिनट
आठ घंटे में - 480 मिनट
अभ्यर्थी- 350
प्रति अभ्यथी समय- करीब 1 मिनट 40 सेकेंड से भी कम

खर्राटे हैं खतरनाक: डा. सूर्यकान्त

केजीएमयू में स्लीप सर्टिफिकेशन कोर्स कार्यशाला होगी आयोजित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में रविवार 22 फरवरी को आईसीएस स्लीप सर्टिफिकेशन कोर्स की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह हैंड्स-ऑन स्लीप कार्यशाला इंडियन चेस्ट सोसाइटी तथा स्नोरिंग एंड स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है।

इस कार्यशाला के वर्कशॉप डायरेक्टर डा. सूर्यकान्त, फाउंडर प्रेसिडेंट, स्नोरिंग एंड स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी एवं डा. अमिता नेने (मुंबई), सेक्रेटरी, इंडियन चेस्ट सोसाइटी हैं। कार्यशाला की कोऑर्डिनेटर डा. ज्योति बाजपेई तथा डा. अभिषेक टंडन हैं।

रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डा. सूर्यकान्त ने बताया कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में देशभर से स्लीप मेडिसिन के विशेषज्ञ एवं चिकित्सक भाग लेंगे। इस कार्यशाला में खर्राटों (स्नोरिंग), ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (ओएसए), स्लीप स्टडी, सी-पैप (सीपीएपी) उपचार, स्लीप स्टडी रिपोर्ट की व्याख्या, विभिन्न पीएपी उपकरणों के उपयोग तथा स्लीप डिसऑर्डर्स के आधुनिक प्रबंधन के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

डा. सूर्यकान्त ने बताया कि खर्राटे को लोग कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं मानते हैं, बल्कि लोगों को लगता है कि खर्राटे लेकर सोने वाला बहुत बढ़िया और चैन की नींद सो रहा है। जबकि खर्राटे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। डा. सूर्यकान्त ने बताया कि खर्राटे लेने वालों को रात भर अच्छी नींद नहीं आती है और उनकी नींद बीच-बीच में खुलती रहती है, साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे शरीर के हर अंग को नुकसान पहुँचता है। खर्राटे के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया (ओएसए), बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

डा. सूर्यकान्त ने सभी गाड़ी चलाने वालों को यह सलाह दी है कि यदि उन्हें खर्राटे आते हैं, तो उन्हें खर्राटे की जांच अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा रात में नींद पूरी न होने के कारण ऐसे लोगों को दिन में बहुत नींद आती है, जिससे उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। दुनिया में लाखों लोगों के रोड एक्सीडेंट खर्राटों की समस्या के कारण ही होते हैं।

इंडियन चेस्ट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डा. सूर्यकान्त ने बताया कि खर्राटे केवल एक सामान्य समस्या नहीं हैं, बल्कि यह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोक तथा सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि स्लीप मेडिसिन के क्षेत्र में प्रशिक्षित चिकित्सकों की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है और इस प्रकार की कार्यशालाएं चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षित करने में अत्यंत उपयोगी हैं।

इस कार्यशाला में विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के साथ-साथ हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्लीप लैब सेट-अप, स्लीप स्कोरिंग, स्लीप स्टडी रिपोर्ट की व्याख्या, पीएपी डिवाइस का उपयोग तथा स्लीप डिसऑर्डर्स के प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल रहेगा। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों के लिए एग्जिट एग्जाम आयोजित किया जाएगा तथा सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। डा. सूर्यकान्त ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाएं चिकित्सकों में स्लीप डिसऑर्डर्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने सभी चिकित्सकों से इस कार्यशाला में भाग लेकर स्लीप मेडिसिन के क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत करने की अपील की। केजीएमयू की कुलपति पद्मश्री डा. सोनिया नित्यानन्द ने 22 फरवरी को होने वाली इस कार्यशाला के लिए डा. सूर्यकान्त एवं डा. अमिता नेने को कार्यक्रम की सफलता हेतु शुभकामनाएं दीं।

बंगाल का भविष्य: धर्म की लहर या प्रगति की राह?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, पर राजनीतिक रणभेरी बज चुकी है। इस बार संकेत साफ हैं-चुनाव विकास बनाम विकास के दावे पर नहीं, बल्कि पहचान, अस्मिता और धर्म की ध्वजा के इर्द-गिर्द घूम सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में प्रस्तावित हिंदू सम्मेलनों को भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक उत्सव भर नहीं, बल्कि चुनावी अवसर में बदलने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी यह समझ लिया है कि यदि चुनाव की जमीन धार्मिक विमर्श पर खिसकती है तो उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोलकाता के न्यू टाउन में 'दुर्गा आंगन' का शिलान्यास और उसे बंगाली अस्मिता से जोड़ने का प्रयास इसी रणनीतिक सजगता का हिस्सा है।

बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वर्ग-संघर्ष, वाम वैचारिकी और सामाजिक न्याय के नारों के इर्द-गिर्द घूमती रही। लगभग तीन दशक तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में रहा। उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था। किंतु 2011 में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नई धुरी बनी-तृणमूल बनाम भाजपा। आज स्थिति यह है कि वाम और कांग्रेस हाशिए पर हैं और मुकाबला दो धूरवों के बीच सिमट चुका है। यही द्विधूरवीयता चुनाव को अधिक तीखा और अधिक पहचान-केन्द्रित बना रही है। भाजपा का अभियान चार प्रमुख सूत्रों पर टिका है-बंगाल में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं की असुरक्षा और भ्रष्टाचार। सीमावर्ती जिलों का उदाहरण देकर यह संदेश गढ़ा जा रहा है कि जनसांख्यिकीय संतुलन बदल रहा है। अवैध घुसपैठ का प्रश्न नया नहीं है, पर उसे इस समय राजनीतिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना, शिक्षक भर्ती घोटाले, हिन्दुओं पर बढ़ते अत्याचार एवं भ्रष्टाचार जैसे प्रसंगों को शासन की विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है-70 प्रतिशत हिंदू मतदाताओं में एक साझा असुरक्षा-बोध निर्मित करना, हिन्दुओं को जागृत करना और उसे मतदान व्यवहार में रूपांतरित करना। आज बंगाल में विकास की सबसे बड़ी बाधा घुसपैठियों का बढ़ना है। घुसपैठियों पर विराम लगाना चाहिए न कि इस मुद्दे पर राजनीति हो।

ममता बनर्जी की चुनौती दोहरी है। एक ओर उन्हें यह संदेश देना है कि वे अल्पसंख्यकों की संरक्षक हैं, दूसरी ओर हिंदू मतदाताओं को यह विश्वास भी दिलाना है कि उनकी आस्था और अस्मिता सुरक्षित है। 2021 के चुनाव में जब भाजपा ने 'जय श्रीराम' के नारे को आक्रामक रूप से उछाला, तब ममता ने 'जय मां दुर्गा' और 'चंडी पाठ' के माध्यम से एक सांस्कृतिक प्रत्युत्तर दिया था। इस बार वे दुर्गा आंगन जैसे प्रतीकों के जरिए यह संकेत दे रही हैं कि बंगाली हिंदू पहचान भाजपा की बपौती नहीं है। वे धर्म को राष्ट्रवाद की बजाय क्षेत्रीय अस्मिता के साथ जोड़ती हैं-"बंगाल अपनी संस्कृति से हिंदू है, पर उसकी राजनीति बहुलतावादी है"-यह उनका अंतर्निहित संदेश है। इसी बीच मुर्शिदाबाद में पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर द्वारा 'बाबरी मस्जिद' के शिलान्यास की पहल ने नई जटिलता जोड़ दी है। इससे मुस्लिम मतदाताओं के भीतर एक अलग धूरवीकरण की संभावना पैदा हुई है। यदि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, तो तृणमूल का गणित प्रभावित हो सकती है। 2021 में उसे लगभग 48 प्रतिशत वोट और 223 सीटें मिली थीं-जिसमें मुस्लिम मतों का एकमुश्त समर्थन निर्णायक था। भाजपा 38 प्रतिशत वोट के साथ 65 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष बनी। ऐसे में यदि मुस्लिम मत 5-10 प्रतिशत भी इधर-उधर खिसकते हैं, तो कई सीटों का परिणाम बदल सकता है और भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ सकती है। यहां प्रश्न केवल गणित का नहीं, राजनीति के चरित्र का भी है। क्या बंगाल का चुनाव धार्मिक पहचान के उभार का प्रयोगशाला बनेगा? या यह प्रयोग अंततः विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के प्रश्नों पर लौटेगा? विडंबना यह है कि जिस बंगाल को कभी देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता था-जहां से उद्योग, शिक्षा और सांस्कृतिक नवजागरण की रोशनी फैलती थी, वह आज अधूरे प्रोजेक्ट्स, धीमी औद्योगिक गति और रोजगार के पलायन से जूझ रहा है। कोलकाता की सड़कों पर अधूरी मेट्रो लाइनें और बंद कारखानों की चुप्पी विकास की उस कहानी को बयान करती हैं, जो राजनीतिक नारों के शोर में दब जाती है। 2011 में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट का राज्य से बाहर जाना एक प्रतीकात्मक मोड़ था। भूमि अधिग्रहण के प्रश्न पर जनसमर्थन पाने वाली राजनीति ने उद्योग के प्रति संशय का वातावरण भी बनाया। पंद्रह वर्षों बाद भी बंगाल बड़े निवेश की प्रतीक्षा में है। युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, और कई राज्यों में उन्हें 'बांग्लादेशी' कहकर अपमानित किए जाने की खबरें आती हैं।

एक सौ करोड़ हिंदुओं का रक्षक डरा हुआ!

ओह! हिंदू राष्ट्र। भला क्यों 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री और एक सौ करोड़ हिंदुओं का रक्षक इतना डरा हुआ! फिर भी नगाड़ा मैं देश और हिंदुओं का रक्षक।

हरिशंकर व्यास

कितनी गजब बात है। क्या दुनिया के किसी देश, किसी संसद में ऐसा हुआ जो पहली बात सदन के नेता को स्पीकर बोले कि आपको भाषण नहीं देना है। और प्रधानमंत्री डर कर राष्ट्रपति अभिभाषण का भी धन्यवाद न करे! इससे भी बड़ा वैश्विक रिकॉर्ड तो देश का प्रधानमंत्री चंद महिला सांसदों के शोर, उनके घेरने को अपने जीवन पर खतरा माने? राहुल गांधी से आंखे मिलाकर अपने समय के ही सेनापति की पुस्तक को लेने से घबराए! और इससे भी अधिक शर्मनाक की राज्यसभा में विपक्ष की खाली बेंचों के आगे प्रधानमंत्री दहाड़े। राहुल गांधी के खानदान के कोसे, उन्हें गांधी के नाम का चोर बताए। अपने समर्थकों की गली में दहाड़ना और विपक्ष से भरी गली से दुबकना, भागना तो वैश्विक ताकत याकि चीन के शी जिनपिंग और अमेरिका के ट्रंप के आगे या तो घिग्घी बंधना, जबरदस्ती गले लगना या मौन रहना, अपमान सहना!

ओह! हिंदू राष्ट्र। भला क्यों 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री और एक सौ करोड़ हिंदुओं का रक्षक इतना डरा हुआ! फिर भी नगाड़ा मैं देश और हिंदुओं का रक्षक। मुझे ही विश्वास नही हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार फरवरी को लोकसभा में इसलिए भाषण नहीं दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। और अपने मुंह से सीधा नहीं बोला। स्पीकर ने बोला कि उन्हें जो जानकारी मिली थी उस आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे चार फरवरी को शाम पांच बजे लोकसभा में भाषण देने नहीं आएं। सो, प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया और उनके भाषण के बगैर, उनकी गैरहाजिरी में लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। भारत का नया रिकॉर्ड बना।

सवाल है क्या स्पीकर को ऐसी सूचना मिली कि महिला सांसद या विपक्ष के दूसरे सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर सकते हैं? आखिर क्या अप्रत्याशित घट सकता था? इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। आखिर विपक्ष के चुने गए सांसदों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर इसमें सचाई है तो जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए नहीं तो यह माना जाएगा कि सरकार विपक्ष के सांसदों की साख खराब करने की कोशिश कर रही है।

सोचें, अगर प्रधानमंत्री भाषण देने आ जाते और उनको भाषण देने से रोक दिया जाता तो क्या हो जाता? जैसे राहुल गांधी 46 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे और नहीं बोल पाए वैसे प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाते। लेकिन वे लोकसभा में जाकर सदन का सामना करते तो उनकी 56 इंच की छाती प्रमाणित होती। वे तो इसकी बजाय लोकसभा छोड़ कर राज्यसभा में चले गए। वहां उन्होंने विपक्षी के वाकआउट के बीच डेढ़ घंटे तक भाषण दिया।

सोचें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर देश पांच सौ करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल खर्च करता हैं। मतलब हर महीने 40 करोड़ रुपए से ज्यादा। यह स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का बजट है। पहले एसपीजी पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार की सुरक्षा भी करती थी। लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई है। एसपीजी अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है। एक व्यक्ति की सुरक्षा पर इतना रुपया खर्च होता है। फिर भी वह व्यक्ति अपने ही देश में, अपनी ही संसद में असुरक्षित महसूस करता है या खतरे से घबरा कर मैदान छोड़ देता है तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या संसद में प्रधानमंत्री को सुरक्षित महसूस कराने के लिए वहां भी एसपीजी की तैनाती कराई जाए? क्या स्पीकर सदन के अंदर एसपीजी तैनात करें, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास बुलेटप्रूफ केबिन बनवाएं या विपक्ष के सांसदों को बाहर निकाल कर हर बार प्रधानमंत्री का भाषण कराया जाए?

याद करें कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे पर थे और फिरोजपुर के कार्यक्रम में शामिल हुए बैगर वे वापिस लौटे थे। प्रधानमंत्री हुसैनीवाला शहीद स्मारक पर जाने के लिए निकले थे। मौसम खराब होने की वजह से वे सड़क के रास्ते जा रहे थे। एक फ्लाईओवर पर लोगों की भीड़ ने जाम लगा रखा था। वहां थोड़ी देर रूकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस लौट आए थे और बठिंडा हवाईअड्डे पर उन्होंने पंजाब के अधिकारियों से कहा था, अपने 'सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया'। सोचें, पंजाब के किसानों की नाराजगी थी और वे प्रदर्शन कर रहे थे। अपने ही लोगों के प्रदर्शन से घबरा कर प्रधानमंत्री वापस लौटे और ऐसा प्रकट किया, जैसे भीड़ उनकी जान लेने के लिए इक_ा थी। और वे किसी तरह से जान बचा कर बठिंडा हवाईअड्डे तक पहुंचे।

सोचें, इतने मजबूत सुरक्षा बंदोबस्तों के बाद भी वे अपनी जान की रक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हैं तो देश के 140 करोड़ नागरिकों और एक सौ करोड़ हिंदुओं की रक्षा कैसे करेंगे? नरेंद्र मोदी ने बारह वर्षों में भारत के नागरिकों को, विपक्ष को, अपनी पार्टी-अपनी जमात को तरह तरह से डराकर कौम को डरपोक, कायर बनाया तो उससे इतनी हिम्मत तो बननी चाहिए कि वे अपनी ही लोकसभा में विपक्ष के आगे हिम्मत दिखाएं, आलोचना सुनें, प्रदर्शन-घेराबंदी को लोकतंत्र का हिस्सा मानें। यह तो न करें कि स्पीकर की आड़ ले कर संसद की भी कर्तव्य पालना न करें।

टिप्पणी

सेल बड़ी छलांग की ओर : बेहतर वित्तीय सूझबूझ से 200 लाख टन बिक्री का तय किया नया लक्ष्य

भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक इस्पात कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), भविष्य के लिए एक नई और मजबूत योजना पर काम कर रही है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना है। सेल का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने ऋण को कम करना है। इससे कंपनी के पास भविष्य के बड़े निवेशों के लिए ज्यादा पैसा और आजादी होगी। कंपनी अपनी उत्पादन लागत को कम करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान दे रही है ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके। सेल अपनी पहुंच बढ़ा रही है ताकि देश में स्टील की बढ़ती मांग का फायदा उठाया जा सके। कंपनी ने अपनी इस तरक्की को मापने के लिए एक लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में जहां बिक्री 179 लाख टन रही, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर के लिए 200 लाख टन का लक्ष्य तय किया गया है।

वित्तीय सूझबुझ और दूरदर्शिता की यह गूंज वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान भी सुनाई दी, जहां निदेशक (वित्त) एवं निदेशक वाणिज्य का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे डॉ. ए.के. पंडा ने कंपनी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि ऋण में कटौती काफी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें अप्रैल-दिसंबर 2025 की नौ महीने की अवधि के दौरान ?5,000 करोड़ का ऋण चुकता किया गया है। पिछले साल 31 दिसंबर, 2025 तक ऋण ?24,852 करोड़ था, जिसके बाद जनवरी 2026 में ?2,000 करोड़ की और कमी आई। इस अनुशासित ऋण कटौती ने वित्त लागत को कम किया है और विकास निवेशों के लिए अवसर पैदा किए हैं। डॉ. पंडा ने बताया, परिचालन दक्षता, इन्वेंट्री लिक्विडेशन, लागत अनुकूलन और मजबूत ट्रेजरी प्रबंधन इत्यादि ने मिलकर बेहतर वित्तीय प्रबंधन को संभव बनाया है।

कंपनी की रणनीति ने पहले ही परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनी की सक्रिय मार्केटिंग पहलों और खुदरा एवं नए ग्राहक समूहों के साथ गहरे जुड़ाव के कारण वित्त वर्ष 2025-26 की नौ महीने की अवधि (अप्रैल25 - दिसंबर25) में बिक्री की मात्रा में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रयास ने अप्रैल 25 - जनवरी 26 के बीच कुल बिक्री को 16.6 मिलियन टन तक पहुँचा दिया, साथ ही महत्वपूर्ण इन्वेंट्री परिसमापन को भी सक्षम बनाया। सेल ने इन-प्रोसेस और तैयार स्टील स्टॉक दोनों को कम करके, सेल ने नकदी प्रवाह को बढ़ाया है और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कम किया, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई।

कंपनी लागत कम करने के लिए ऑपरेशनल लिवर्स को भी तेज किया जा रहा है। सालाना मैनपावर में कमी से प्रति टन कार्मिक लागत दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है। इसके साथ ही, सेल अनुपालन की जरूरतों के साथ-साथ लागत कम करने के लिए भी अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ऊर्जा व्यय में संरचनात्मक बचत हो रही है। ये उपाय प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करते हुए कंपनी के व्यापक स्थिरता एजेंडे के साथ मेल खाते हैं।

कंपनी के भविष्य के विज़न पर सेल के निदेशक (वित्त) एवं निदेशक वाणिज्य का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे डॉ. ए.के. पंडा ने कहाः कंपनी कर्ज कम करके, इन्वेंट्री की अधिक कुशलता से प्रबंधन करके और केंद्रित मार्केटिंग पहलों के मध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार करके, विस्तारीकरण की तैयारी के साथ-साथ अपनी नींव को मजबूत कर रहा है। बढ़ती मांग, एक मजबूत कैपेक्स पाइपलाइन और स्थिरता व ग्रीन स्टील के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ, हम वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 200 लाख टन की बिक्री हासिल करने और आने वाले वर्षों में और भी ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के प्रति आश्वस्त हैं - जो आज की ताकत को कल के अवसर में बदल देगा।

ब्लॉग

शंकराचार्य के साथ ऐसा बरताव

अजीत द्विवेदी

यह संयोग नहीं है कि करीब तीन साल तक आधा दर्जन से ज्यादा पिछड़ी जाति के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा करने के बाद भाजपा ने अगड़ी जाति के नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उसके बाद यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के नाम पर ऐसा नियम पेश किया, जिसके खिलाफ पूरा सवर्ण समाज आंदोलित हुआ। यह भी संयोग नहीं है कि एक शंकराचार्य को माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान से रोका गया और 11 दिन के अनशन के बाद भी किसी ने अनशन समाप्त कराने का प्रयास नहीं किया। उलटे शंकराचार्य की साख बिगाड़ने और उनके पट्टाभिषेक को विवादित साबित करने वाले काम हुए।

शंकराचार्य को मेला प्रशासन ने नोटिस देकर उनकी पदवी के बारे में सफाई मांगी और दूसरी नोटिस में उनको धमकाया कि जमीनें ले ली जाएंगी और सुविधाएं छीन ली जाएंगी। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी अगर हिंदू धर्म की धार्मिक व आध्यात्मिक परंपरा के शिखर पर बैठे चार में से एक शंकराचार्य को धमकी दे रही है तो वह अनायास नहीं हो सकता है।

संभव है कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ रविवार, 18 जनवरी को जो घटना हुई वह अचानक हो गई हो। वे पालकी से स्नान के लिए जा रहे थे और भीड़ बहुत होने की वजह से उनको रोका गया हो। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वह एक राजनीतिक योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य से पुरानी बातों और उनके बयानों का बदला लिया जा रहा है और उस पद के महत्व को हमेशा के लिए समाप्त किया जा रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके विवादित बयानों से अछूते नहीं रहे हैं। उन्होंने पिछले साल प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ और लोगों की मौत को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया था।

ध्यान रहे भारत में शंकराचार्य का पद कभी भी ईसाई धर्म के वेटिकन के पोप की तरह या इस्लाम धर्म के मौलानाओं, शाही इमामों या खलिफाओं की तरह नहीं रहा है। वे हिंदू धर्म के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी करते हैं और उनके प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हिंदू समाज भी उनके हिसाब से अपना जीवन चलाने के लिए बाध्य नहीं होता है। वे सनातन की आध्यत्मिक परंपरा के सर्वोच्च प्रतिनिधि होते हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत दिया वे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत के एक राष्ट्र राज्य के तौर पर उभरने से पहले शंकराचार्य द्वारा निर्धारित की गई भौगोलिक सीमा के चारों कोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिहाज से उनका अपना महत्व है।

शंकराचार्यों की बातों को हिंदू जीवन पद्धति में हस्तक्षेप के तौर पर कभी नहीं देखा गया लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ शंकराचार्यों और अन्य धर्मगुरुओं या कथावाचकों का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ा है। अपने समर्थकों या प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने के लिए वे लोकप्रिय भावना के अनुरूप बयानबाजी करने लगे। इसमें कथावाचक और धर्म को कारोबार बनाने वालों ने तो सहज रूप से सबसे शक्तिशाली दल और सरकार के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया लेकिन आध्यात्मिक परंपरा का पालन करने वाले शंकराचार्यों ने ऐसा नहीं किया।

तभी जब सौंदर्यीकरण के नाम पर मंदिर तोड़े गए तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब से कर दी या जब अयोध्या में राममंदिर संपूर्ण नहीं हुआ था, उसका शिखर नहीं बना था, उस पर ध्वजा नहीं फहराई गई थी तो चारों शंकराचार्य उसके उद्घाटन में शामिल होने नहीं गए। हो सकता है कि इससे राजसत्ता में नाराजगी हुई हो। राजसत्ता ने धर्मसत्ता को अपने लिए चुनौती की तरह देखा हो और अविमुक्तेश्वरानंद के पुराने राजनीतिक बयानों को आधार बना कर उनके बहाने शंकराचार्य की समूची व्यवस्था की साख बिगाड़ने और उसका महत्व कम करने का प्रयास किया जा रहा हो।

यह भी हो सकता है कि प्रयागराज में माघ मेले में हुई घटना के बहाने सबक देने की कोशिश हुई हो ताकि आगे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्मसत्ता कभी भी राजसत्ता का विरोध न करे। शंकराचार्य इस बात को समझ रहे हैं तभी धीरे धीरे बाकी तीन शंकराचार्यों, द्वारिका की शारदा पीठ के सदानंद जी महाराज, पुरी की गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद जी महाराजा और श्रृंगेरी पीठ के स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। पहले अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक को लेकर कुछ संशय था तो उसे दरकिनार करके तीनों शंकराचार्य उनके समर्थन में उतरें हैं।

ध्यान रहे शंकराचार्य का चयन शंकराचार्य ही करते हैं। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा यह होता है कि बाकी शंकराचार्य उसका समर्थन करें। इस लिहाज से अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति विवादित नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि उनके गुरू और शारदा पीठ व ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उनकी नियुक्ति की थी। ज्योतिषपीठ विवाद में इसलिए फंसा क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती दो पीठों के शंकराचार्य थे। सवाल उठाया गया कि एक व्यक्ति दो पीठ का शंकराचार्य नहीं हो सकता है। इसी तरह से यह भी परंपरा है कि कोई भी पीठ खाली नहीं रहेगी। सो, अगर अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं माना जाए तो क्या तीन साल से ज्यादा समय से ज्योतिषपीठ खाली है?

बहरहाल, सरकार को इन तमाम बातों की जानकारी है। इसके बावजूद शंकराचार्य से जुड़े विवाद को बढ़ने दिया गया और उनको ससम्मान स्नान करा कर विदा करने और विवाद समाप्त करने की बजाय उनको धमकाया गया। सोचें, जो सरकार या जो पार्टी हत्या और बलात्कार के दोषी ठहराए गए या आरोपी बनाए गए कथावाचकों व कथित संतों को समस्त सुविधाएं देती हो वह एक शंकराचार्य के साथ ऐसा बरताव करे तो क्या इसे सामान्य घटना मान सकते हैं? असल में देश हजारों की संख्या में जो कथावाचक पैदा हुए हैं या कथित साधु, संत, बाबा, महामंडलेश्वर पैदा हुए हैं उनका स्वार्थ है। वे ज्यादा से ज्यादा शिष्य या श्रोता बनाने के लिए काम करते हैं और पैसे कमाने, राजनीति को प्रभावित कर सकने वाली हस्ती बनाने और तमाम भौतिक सुख सुविधाएं हासिल करने के लिए काम करते हैं। इनमें कुछ अपवाद भी होंगे लेकिन ज्यादातर ऐसे ही हैं। ऐसे लगभग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और दिन रात प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों का गुणगान करते हैं। शंकराचार्य ये काम नहीं करते हैं और न कर सकते हैं। वे धर्म, आध्यात्म और समाज से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाते हैं, जिससे सरकार असहज होती है।

तभी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा को समाप्त किया जा रहा है। उनकी जगह कथावाचकों व अनाप शनाप बयानबाजी करने और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को बढ़ाने का काम करने वाले कथित साधु संतों का महिमामंडन किया जा रहा है। एक बारीक बात यह है कि शंकराचार्य पारंपरिक रूप से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह से यूजीसी के नए नियमों का मकसद पिछड़ी जातियों को एक संदेश देना है उसी तरह शंकराचार्य को टारगेट करके भी पिछड़ी जातियों को संदेश दिया जा रहा है कि सरकार पारंपरिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त कर रही है।

असल में भाजपा को लग रहा है कि कांग्रेस, सपा, राजद जैसी विपक्षी पार्टियां 'जितनी आबादी, उतना हक का नारा देकर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी आबादी को अपने साथ जोड़ रही हैं। विपक्ष का यह वोट अपनी ओर करने की दीर्घकालिक योजना के तहत भाजपा नए प्रयोग कर रही है। वह कुछ आगे बढ़ेगी और कुछ पीछे हटेगी लेकिन यह प्रयोग चलेगा। उसको लग रहा है कि अंत में सवर्ण मतदाताओं के पास भाजपा के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इसलिए वह एससी, एसटी और ओबीसी वोट सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। इसका एक बड़ा हिस्सा पहले से भाजपा के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ी जाति का प्रतीक चेहरा हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का भी चेहरा हैं। इसलिए यह मैसेज भी दिया जा रहा है कि उनके रहते शंकराचार्यों की क्या जरुरत है! राजनीति में अक्सर नेता यह गलती करते हैं। वे अपना मूल छोड़ कर दूसरे का वोट हथियाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में अपना मूल भी गंवा देते हैं।

डार्कवेब पर गंदा खेल, 47 देशों में बेचे अश्लील वीडियो... 34 मासूमों से दरिंदगी करने वाले पति-पत्नी को कैसे मिली फांसी की सजा?

आर्यावर्त संवाददाता

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाले मामले में फैसला सुनाते हुए चित्रकूट के निलंबित जूनियर इंजीनियर रामभवन कुशवाहा और उनकी पत्नी दुर्गावती को मौत की सजा सुनाई। यह मामला बच्चों के यौन शोषण, अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाने तथा उन्हें डार्कवेब पर बेचने से जुड़ा है, जिसमें 34 मासूम बच्चे शिकार बने, 74 गवाहों की गवाही हुई और 47 देशों का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया।

बांदा अदालत के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर 2020 को हुई, जब इंटरपोल ने दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय को एक विस्तृत ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज की। शिकायत में बताया गया कि आरोपी रामभवन तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों से डार्कवेब के जरिए बच्चों के अश्लील वीडियो और फोटो 47 देशों में बेच रहा था। इंटरपोल, जो 195 देशों में सक्रिय है, की यह शिकायत बाल यौन शोषण के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह के पर्दाफाश की दिशा में पहला कदम साबित हुआ। सीबीआई ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू की।

दरिंदगी के 34 वीडियो और 679 तस्वीरें

नवंबर 2020 में सीबीआई की टीम ने बांदा के नरैनी कस्बे में रामभवन और दुर्गावती को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें 34 वीडियो और 679 तस्वीरे थीं। जांच में पता चला कि आरोपी बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और आसपास के इलाकों से तीन साल तक के छोटे बच्चों को निशाना बनाते थे। वे बच्चों का यौन शोषण करते हुए वीडियो और फोटो बनाते थे और इन्हें डार्कवेब, सोशल मीडिया साइट्स, वीडियो प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइटों पर बेचते थे।

74 गवाहों को किया गया था पेश

सीबीआई के सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने इस मामले की जांच की, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया और मानवता को शर्मसार किया। अदालती कार्रवाई के दौरान 5 जून 2023 से 74 गवाहों को पेश किया गया, जिनमें 24 पीड़ित बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों की गवाही ने मामले की गंभीरता को और उजागर किया। सीबीआई के लोक अभियोजक दारा सिंह मीणा ने बताया, "इंटरपोल से मिली तीन ई-मेल शिकायतों के बाद हमने महीनों तक गहन जांच की। हमने ऐसे पुख्ता सबूत जुटाए जो साबित करते हैं कि आरोपी इस जघन्य अपराध में पूरी तरह लिप्त थे।

दोषियों को मिली फांसी की सजा

बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यह अपराध इतना घिनौना है कि मौत की सजा ही न्यायसंगत है। बांदा अदालत ने पहले भी हत्या, अपहरण और गैंग रेप जैसे मामलों में करीब 23 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन किसी महिला को यह सजा पहली बार मिली है। पिछले छह महीनों में जज मिश्रा की अदालत ने तीन मामलों में चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है, जिसमें यह महिला आरोपी भी शामिल है। यह मामला न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में बाल यौन शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मिसाल बनेगा।

फर्जी चिकित्सकों की जांच से बच रहे अधिकारी

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर फर्जीवाड़े का गोरख धंधा खुले आम चल रहा है। फर्जी डिग्री बनवाकर बने फर्जी डॉक्टर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत कोई कार्यवाही नहीं कर रहा हैं। कई चिकित्सक बिना मानक के और बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम व पाली क्लीनिक, डिस्पेंसरी खोलकर बैठे हैं मानो यह अस्पताल न होकर किराने की दुकान होकर अपने ही अस्पतालों में पैथोलॉजी खोलकर जांच के नाम मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। सूत्र बताते हैं की आशा कार्यकत्रियों की मिली भगत भी इन खेल को बढ़ावा दे रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत की आशा लालच में आकर वे मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम और क्लीनिक में भर्ती करती हैं और मोटी रकम वसूलती हैं । चौंकाने वाली बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत के महज 100 मीटर के अंदर में ही कई ऐसे नर्सिंग होम क्लीनिक सक्रिय है, जहां मरीजों की जिंदगी से खेल खेला जा रहा है मरीज आते हैं तो इस तरह डराया जाता है कि उनका पूरा दिन का खर्च वसूल हो जाता है। सरकार ने आशा कार्यकत्रियों की नियुक्ति स्वास्थ्य योजनाओं को अपने क्षेत्र में घर-घर तक पहुंचाने और गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के लिए की थी लेकिन अब यह नेटवर्क फर्जी अस्पतालों का सहायक बन गया है। स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत के अधीक्षक की चुप्पी और मिली भगत के बिना यह खतरनाक धंधा फल फूल नहीं सकता, नियमानुसार एक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 वर्ष से ज्यादा रहने का अधिकार नहीं है, अब देखना है कि प्रशासन कब तक कान में तेल डाले आंख मूंद कर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं।

जयमाला मंच पर दूल्हे ने दुल्हन को पीटा, फिर बराती-घराती में चलीं कुर्सियां

आर्यावर्त संवाददाता

बाराबंकी। यूपी के बाराबंकी में शुक्रवार रात शादी समारोह में जयमाला के दौरान सेल्फी लेने से नाराज दूल्हे ने दुल्हन को पीट दिया। घटना के बाद बराती और घराती पक्ष आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। समझौते के बाद देर रात शादी की रस्में पूरी कराई गईं।

घटना रामनगर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर कस्बा की है। यहां के निवासी शत्रुघ्न मूर्ति बनाने का काम करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी बहराइच के मुराइनपुरवा निवासी विशाल के साथ तय की थी। शुक्रवार शाम तय तिथि पर बरात धूमधाम से पहुंची। द्वार पूजा की रस्म संपन्न हो गई। बराती नाच-गाने में व्यस्त थे।

दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई

इसके बाद जयमाला के लिए दुल्हन मंच पर पहुंची तो वहां भीड़ एकत्र हो गई। दूल्हे के साथ लोग सेल्फी लेने लगे। गांववालों के मुताबिक, दूल्हे ने कई बार मना किया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। इसी बात से नाराज होकर दूल्हा आपा खो बैठा। उसने दुल्हन पर हाथ उठा दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। एक-दूसरे पर कुर्सियां बरसाईं। इससे कई कुर्सियां टूट गईं।

देर रात विवाह की रस्में पूरी कराई गईं

घटना से समारोह स्थल पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। दुल्हन पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हा नशे में था। बाद में आपसी बातचीत और नुकसान की भरपाई के आश्वासन पर देर रात विवाह की शेष रस्में पूरी कराई गईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रात में खटपट की आवाज सुनकर जागा युवक, सामने खड़ी थी 'मौत'...सीने में गोली मारकर हत्या

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहांआधी रात घर में घुसे बदमाशों ने युवक के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई।

मृतक की पहचान 40 वर्षीय जोगेंद्र लोधी के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ प्रगति नगर इलाके में रहता था। बताया जा रहा है कि बदमाश लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए थे, लेकिन विरोध होने पर उन्होंने गोली चला दी।

रात करीब एक बजे हुई वारदात

परिजनों के मुताबिक घटना रात करीब एक बजे की है। जोगेंद्र अपने घर के बरामदे में सो रहा था और पास में पत्नी अनीता भी मौजूद थी। तभी मकान की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। शक होने पर दोनों पति-पत्नी सीढ़ियों के जरिए छत की तरफ जाने लगे। बताया गया कि जैसे ही जोगेंद्र सीढ़ियों के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद दो बदमाशों में से एक ने उस पर फायर कर दी। बदमाश ने सीने में गोली मारी, जिससे वह वहीं गिर पड़ा। गोली लगते ही उसकी हालत गंभीर हो गई और कुछ ही देर में मौत हो गई। पत्नी ने जब शोर मचाया तो बदमाश मौके से भाग निकले। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी घर के बाहर इकट्ठा हो गए। परिवार में चीख-पुकार मच गई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिय भेज दिया है।

पुलिस जांच में जुटी, केस दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सुभाषनगर थाने के इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला लूटपाट की कोशिश का लग रहा है। बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि टीमों को बदमाशों की तलाश में लगाया गया है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात में पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। वहीं मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

फागुन आया , सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। फागुन का महीना आग या है । जिले भर के ग्रामीणों क्षेत्र में प्रकृति मानो अपने पूरे श्रृंगार में उतर आयी है। चारों तरफ पतझड़ की उदासी को पीछे छोड़ खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर बिछ गयी है और गेहूं की हरी-भरी बालियां हवा के झोंकों संग लहराने लगी हैं। ज्ञात हो कि यह दृश्य केवल आंखों को सुकून ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य के जीवन में भी नई ऊर्जा और उमंग भर देता है।फागुन की यह बहार ग्रामीण अंचल में एक अलग ही उत्सव का माहौल बना देती है। खेतों में खिले सरसों के फूल वातावरण को खुशबू और रंगों से भर देते हैं। वहीं गेहूं की हरियाली किसानों के चेहरे पर उम्मीद और खुशी की चमक ला देती है। खेतों में काम करते किसान और मजदूर भी इस मौसम में अलग ही उत्साह के साथ नजर आते हैं। प्रकृति का यह परिवर्तन केवल खेती-बाड़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गांवों में त्योहारों की रौनक भी बढ़ जाती है। फागुन के साथ ही होली का पर्व नजदीक आता है, जिससे हर घर में खुशियों की तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के मन में उमंग का संचार होता है। सरसों के पीले फूल और गेहूं की हरियाली यह संदेश देती है कि जीवन में हर पतझड़ के बाद नई बहार जरूर आती है। यही कारण है कि फागुन का यह मौसम लोगों के लिए सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि नई उम्मीद, उत्सव और आनंद का प्रतीक बन जाता है। फागुन की यह बहार गांव-देहात में खुशियों का रंग बिखेर रही है और हर दिल में नए उत्सव की दस्तक दे रही है।

बाजार गई थी मां, अस्पताल में डॉक्टर पिता...घर में बेटे ने कर लिया सुसाइड, फंदे पर लटका मिला शव

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां मुंढापांडे क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) परिसर स्थित सरकारी आवास में एक 15 साल के लड़के ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। लड़के का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के पंखे से लटका मिला। घटना की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए।

मृतक की पहचान यश कुमार (15) के रूप में हुई है। वह कक्षा 9 का छात्र था और सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई करता था। परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, यश एक शांत स्वभाव का छात्र था। उसकी दिनचर्या सामान्य थी और घटना वाले दिन भी वह रोज की तरह घर पर ही मौजूद था।

डॉक्टर के बेटे ने किया सुसाइड

जानकारी के मुताबिक, यश के पिता कुलदीप कुमार भारती मुंढापांडे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हैं। घटना के समय वह अपनी ड्यूटी पर थे, जबकि उसकी मां किसी जरूरी काम से बाजार गई हुई थीं। उस दौरान घर में यश अकेला था। देर शाम जब उसकी मां वापस लौटीं तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद है। काफी देर तक आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अनहोनी की आशंका होने पर दरवाजा खुलवाया गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया, अंदर का दृश्य देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यश का शव पंखे से लटका मिला।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना तुरंत थाना मुंढापांडे पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए सबूत जुटाए । पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही असली वजह का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में छात्र ने यह कदम उठाया।

आगामी जनगणना के तैयारियों की हुई समीक्षा

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। प्रथम जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक प्रमुख जनगणना अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में अवगत कराया गया कि जनगणना 2027 का प्रथम चरण 22 मई 2027 से 20 जून 2027 तक संचालित किया जाएगा। इसके पूर्व स्व-गणना की सुविधा 07 मई से 21 मई 2027 तक उपलब्ध रहेगी। जिलाधिकारी ने स्व-गणना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक नागरिक स्वयं गणना कर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सहभागिता सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद के लिए मास्टर ट्रेनर्स का 4 दिवसीय प्रशिक्षण 24 से 27 फरवरी 2027 तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 146 फील्ड ट्रेनर्स की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जो मार्च माह में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अप्रैल में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत जनपद में 8000 से अधिक ग्रामीण गणना ब्लॉक एवं 1000 से अधिक शहरी गणना ब्लॉक निर्धारित किए जाएंगे। इसके लिए 9800 से अधिक प्रगणक ब्लॉक तथा 1600 से अधिक पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। यह भी अवगत कराया गया कि जनगणना 2027 पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी।

'मक्का-मदीना' का स्टीकर, प्रीमियम बताकर बेच रहे लोकल खजूर, मुरादाबाद का वीडियो हैरान कर देगा

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। कहीं आप भी तो नहीं खा रहे 'नकली' महंगी खजूर... मुरादाबाद में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों की बढ़ती मांग का फायदा उठाते हुए कुछ थोक व्यापारियों की ओर से कम गुणवत्ता वाली खजूर को नामी विदेशी ब्रांडों के डिब्बों में पैक कर ऊंचे दामों पर बेचे जाने का मामला सामने आया है। इस कथित गोरखधंधे का खुलासा एक वायरल वीडियो से हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि खराब किस्म के खजूर को प्लास्टिक कंटेनरों में भरकर उन पर मक्का-मदीना जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का स्टीकर चिपकाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, 50 से 200 रुपये प्रति किलो की साधारण खजूर को दोबारा पैक कर 800 से 1000 रुपये प्रति किलो तक के प्रीमियम विदेशी खजूर के रूप में बाजार में बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद मंडी से इस तरह तैयार नकली ब्रांडेड खजूर आसपास के जिलों में ट्रकों के जरिए सप्लाई की जा रही है, जिससे संबंधित कारोबारियों को करोड़ों रुपये का अवैध लाभ हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला केवल धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजेदारों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ भी माना जा रहा है। रमजान में रोजा खोलने के लिए खजूर का विशेष महत्व होता है, ऐसे में घटिया गुणवत्ता के उत्पाद को विदेशी और प्रीमियम बताकर बेचना उपभोक्ताओं के विश्वास पर सीधा प्रहार है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी में गुणवत्ता की नियमित जांच और ब्रांड सत्यापन की व्यवस्था न होने के कारण इस प्रकार की हेराफेरी लंबे समय से चल रही हो सकती है।

प्रशासन ने जांच के दिए आदेश

वायरल वीडियो सामने आने के बाद मंडी परिसर में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि पैकिंग में नाबालिगों से श्रम तो नहीं कराया जा रहा, क्योंकि ऐसा पाया जाने पर बाल श्रम कानूनों के तहत भी कड़ी कार्रवाई संभव है। मुरादाबाद मंडल के बाजारों में रमजान के कारण विभिन्न प्रकार की खजूर की मांग बढ़ी हुई है। ऐसे में नकली ब्रांडेड उत्पादों की आपूर्ति से उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। खरीदारों का कहना है कि वे अब पैकिंग और ब्रांड पर भरोसा करने से पहले सावधानी बरतेंगे। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन से मंडी में नियमित छापेमारी, गुणवत्ता जांच और ब्रांडिंग नियमों के कड़ाई से पालन की मांग की है।

क्या बोले अधिकारी?

मुरादाबाद में वायरल हो रहे कथित नकली खजूर पैकिंग वीडियो को लेकर प्रशासन और समाज के जिम्मेदार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त राजवंश श्रीवास्तव ने कहा कि संबंधित वीडियो उन्हें प्राप्त हो गया है। इसे संज्ञान में ले लिया गया है और इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

'लोगों के विश्वास के साथ सीधा खिलवाड़'

वहीं, स्थानीय निवासी मोहम्मद शाहजी ने इस पूरे मामले को रोजेदारों की आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सस्ती खजूर को महंगी बताकर पैक कर बेचा जा रहा है, वह लोगों के विश्वास के साथ सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि रोजेदार दिनभर मेहनत और संयम से रोजा रखते हैं और इफ्तार में खजूर से रोजा खोलते हैं। ऐसे में यदि उनके सामने नकली या घटिया गुणवत्ता की खजूर परोसी जाए, तो यह उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने जैसा है। मुरादाबाद के मौलाना नाजिम अशरफी ने कहा कि किसी वस्तु को कुछ और बताकर बेचना इस्लाम में स्पष्ट रूप से धोखा माना गया है। उन्होंने कहा कि रमजान जैसे पवित्र महीने में इस तरह का कृत्य और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि इसमें रोजेदारों की आस्था और भरोसे दोनों को ठेस पहुंचती है।

परिश्रम और तैयारी से ही मिलती है सफलता

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान द्वारा शनिवार को "करियर उन्नयन एवं मूट कोर्ट मार्गदर्शन" विषय पर विशेष व्याख्यान एवं कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वर्ष 2008 के चर्चित आरुषि तलवार हत्याकांड पर आधारित आभासी न्यायालय की नाट्य प्रस्तुति रही।अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कहा कि आभासी न्यायालय जैसी शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, अभिव्यक्ति कौशल एवं विधिक दक्षता को सुदृढ़ बनाती हैं। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक प्रशिक्षण से विद्यार्थी भविष्य की पेशेवर चुनौतियों के लिए पूर्णतया तैयार होते हैं। मुख्य वक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को व्यावसायिक उन्नति, आभासी न्यायालय की उपयोगिता तथा विधि व्यवसाय में सफलता के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने नियमित अध्ययन, नवीनतम विधिक ज्ञान एवं न्यायालयीन अनुशासन के महत्व पर विशेष बल दिया।विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एच. वशिष्ठ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक सफल अधिवक्ता बनने के लिए वाद की गहन तैयारी, तथ्यों की स्पष्ट समझ तथा पेशेवर नैतिकता अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों ने न्यायालयीन प्रक्रिया, साक्ष्य परीक्षण, जिरह तथा विधिक तर्कों का प्रभावशाली प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रस्तुति के माध्यम से छात्र-छात्राओं को वास्तविक न्यायिक कार्यवाही की अनुभूति प्राप्त हुई तथा उनके आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वित्त अधिकारी आत्मा प्रकाश धर द्विवेदी, कुलसचिव केशलाल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया ।संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विनोद कुमार ने अतिथियों का स्वागत, संचालन डॉ. अनुराग मिश्र एवं आभार डॉ. दिनेश सिंह ने व्यक्त किया। आरुषि तलवार हत्याकांड पर आधारित आभासी न्यायालय में विभिन्न भूमिकाओं में विधि के विद्यार्थी अपर्णा उपाध्याय, प्राची जायसवाल, प्रतीक्षा शुक्ला, अजीत कुमार, ईशांत यादव, अभितांश यादव, अजय बिंद, शिवानी दुबे, अनन्या अग्रहरी, स्नेहा मिश्रा, वैष्णवी त्रिपाठी, हिमांशु, सन्दल फिरदौस अंसारी रहें।

बालों में चिपका हो च्यूइंगम या कपड़े पर मेंहदी का दाग...ये 5 हैक्स बनाएंगे काम

घर में कई बार बच्चे खेल-खेल में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं, जिससे निजात पाना बहुत ही मशक्कत वाला काम हो जाता है। इसी तरह से घर में काम करने के दौरान भी कुछ कामों में बहुत टाइम और एनर्जी चली जाती हैं। आपके ऐसे ही कामों को आसान बनाएंगे यहां पर दिए गए 5 सिंपल से हैक्स।

बालों में च्यूइंगम चिपकनाः अगर बालों में च्यूइंगम चिपक जाए तो इसे हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग उतने बाल ही काट देते हैं। इसी तरह से अगर आपके फेवरेट ड्रेस पर च्यूइंगम चिपक जाए तो झल्लाहट हो जाती है। इसे छुड़ाने के लिए आपको बस उसके ऊपर कुछ देर के लिए आइस क्यूब्स रखना है। इससे च्यूइंगम काफी सख्त हो जाती है और आसानी से हट जाती है। मेहंदी का दाग कपड़े परः अगर आपके कपड़ों पर मेहंदी के दाग लग जाएं तो इसे छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक इनो का पैकेट लेना है। और गर्म पानी में इसे डालें। आप इस घोल को मेहंदी के दाग पर डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे दाग हट जाता है।

माइक्रोवेव की सफाईः अगर आपके माइक्रोवेव में अजीब सी महक आने लगी है या फिर चिकनाई जम गई है तो इसे साफ करने के लिए आप एक कटोर में पानी डालकर इसमें नींबू का रस और बेकिंग सोडा डालें। इसे माइक्रोवेव में 1 से दो मिनट तक गर्म करें। इससे पूरे में भाप फैल जाती है, जिससे स्मेल दूर होगी। आप कपड़े से इसे पोंछ लें। आप इस पानी में कपड़ा भिगोकर भी माइक्रोवेव साफ कर सकते हैं।

सिंक क्लीनिंगः किचन सिंक को साफ करना भी किसी झंझट से कम नहीं होता है। इसमें पड़े दाग-धब्बे हटाने के लिए सिंपल हैक है कि आप सिंक में बेकिंग सोडा छिड़क दें और फिर इस पर वाइट विनेगर डालें। इसमें झाग बन जाएंगे। इसे 10 मिनट ऐसे ही रहने दें और फिर स्क्रबर से रगड़कर गर्म पानी से साफ करें।

दीवार के दाग हटानाः बच्चे अक्सर खेल-खेल में दीवार पर क्रेयॉन्स से ड्राइंग बना देते हैं। इसको साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए।पहले गीले कपड़े से दीवार को नम करें। फिर दागों पर उंगली से टूथपेस्ट लगा दें। कम से कम 10 मिनट के बाद आप गुनगुने पानी में भीगे गीले कपड़े से दाग साफ कर लें।

वजन घटेगा, चेहरा होगा चमकदार...पिएं ये मैजिकल पानी, भाग्यश्री ने बताया

एक्ट्रेस भाग्यश्री 50 प्लस एज में भी बला की खूबसूरत हैं और उनकी फिटनेस भी कमाल की है। इसके पीछे की वजह है हेल्दी खानपान और सही रूटीन फॉलो करना। उन्होंने एक मैजिकल वाटर बताया है जो वेट लॉस से लेकर स्किन को चमकाने में भी हेल्पफुल रहेगा।

90's में लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री की फैन फॉलोइंग लिस्ट आज भी बहुत लंबी है। वह 56 की हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी 30 की एज जैसी है। एक्ट्रेस इसके लिए कड़ी मेहनत भी करती हैं जैसे वर्कआउट करना, न्यूट्रिएंट्स रिच फूड्स का सेवन और स्किन केयर में भी नेचुरल चीजों का यूज करना। आज के टाइम में यंग लोग भी स्किन से जुड़ी दिक्कतों और बढ़ते वजन से काफी परेशान रहते हैं, लेकिन अगर छोटे-छोटे कदम भी बढ़ाए जाएं तो अच्छी फिटनेस और ग्लोइंग-हेल्दी स्किन पाई जा सकती है। एक्ट्रेस भाग्यश्री ने एक मैजिकल वाटर बताया है जो आपको फिट रखने में मदद करेगा और चेहरा भी चमकाएगा।

चमकदार, स्वस्थ त्वचा और फिट बॉडी ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको न सिर्फ प्रेजेंटेबल दिखाती हैं, बल्कि अंदर से कॉन्फिडेंट भी महसूस करवाती हैं। बाहरी देखभाल के लिए मार्केट में कई प्रोडक्ट मौजूद हैं लेकिन अगर अंदर से स्ट्रांग बनना हो या फिर फिटनेस को सुधारना हो और त्वचा को नेचुरली स्वस्थ बनाना हो तो इसमें पोषण अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर मैजिकल वाटर बनाने का तरीका और इसके कितने हैं फायदे।

कैसे बनाएं ये मैजिकल वाटर?

आपकी रसोई में मौजूद सिंपल से इनग्रेडिएंट्स भी आपको हेल्दी बनाए रखने में बहुत कारगर होते हैं और इससे आपकी त्वचा पर भी बहुत फर्क नजर आता है। एक्ट्रेस भाग्यश्री कहती हैं कि गुनगुने पानी में ये सारी चीजें आधे घंटे के लिए रख दें और फिर इस पानी को पिएं। दो सप्ताह तक पानी को रोजाना पीने से आपको बदलाव देखने को मिलेगा।

कैसे मिलेगा फायदा?

एक्ट्रेस भाग्यश्री का कहना है कि इस पानी में डाली जाने वाली हर एक चीज अलग-अलग फायदे देती है, जैसे हरी इलायची और पुदीना आपके शरीर को ठंडा रखते हैं। दालचीनी और लौंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे वेट लॉस में हेल्प मिलती है। इससे आप संक्रमण से भी बचे रहते हैं। तेज पत्ता और चक्रफूल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, साथ ही इंफ्लामेशन यानी सूजन को कम करते हैं। इस तरह से ये पानी आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा, त्वचा को हेल्दी बनाएगा और वेट भी कंट्रोल होगा।

हर इनग्रेडिएंट में औषधीय गुण

तेजपत्ता से लेकर लौंग, इलायची और चक्रफूल तक औषधीय गुणों से भरपूर माने जाते हैं। हेल्थ लाइन के मुताबिक, लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है। ये बैक्टीरिया को नष्ट करने से लेकर ब्लड शुगर रेगुलेट करने और आपकी हड्डियों की हेल्थ सुधारने तक में फायदेमंद है। वहीं पबमेड में छपी जानकारी कहती हैं कि तेज पत्ता में भी एंटीवायरल से लेकर एंटीम्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करने में हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह से पुदीना, चक्रफूल और हरी इलायची भी विटामिन-मिनरल का सोर्स हैं।

जाती ठंड में बच्चे को जुकाम का डर! इन बातों का रखें ध्यान

बदलते मौसम में ठंड लगने यानी खांसी-जुकाम की शिकायत के होने का डर ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चे और बुजुर्गों को इसके होने का डर बना रहता है। जानें बदलते मौसम में कोल्ड और कफ से कैसे बचा जाए और खानपान कैसा होना चाहिए।

फरवरी में ही हल्की गर्मी महसूस होने लगी है और लोगों ने कपड़े पहनना भी कम कर दिया है। घरों में रजाई और कंबल स्टोर किए जा रहे हैं। जाती ठंड में खांसी-जुकाम की दिक्कत ज्यादातर लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। इसका अहम कारण लो इम्यूनिटी है। मौसम में बदलाव के दौरान जरा सी लापरवाही कुछ लोगों को भारी पड़ जाती है। दरअसल, कोविड के समय जन्मे बच्चों में अधिकतर लो इम्यूनिटी का शिकार हैं। इस वजह से उन्हें हर 15 से 20 दिन में दोबारा खांसी-जुकाम हो जाती है। कुछ बच्चों को खांसी-जुकाम के साथ बुखार भी आज जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खासतौर पर बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए।

बच्चों को कोल्ड-कफ से बचाने के लिए पेरेंट्स उन्हें एंटीबायोटिक देते हैं। ये दवा उनके डाइजेशन को कमजोर बनाती है। चलिए आपको बताते हैं कि बदलते मौसम में बच्चे को सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए कौन-कौन से तरीके आजमाने चाहिए।

बदलते मौसम में क्यों बीमार पड़ जाते हैं बच्चे

एक्सपर्ट्स के मुताबिक बदलता मौसम बच्चों की इम्यूनिटी और शरीर पर सीधा असर डालता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता। ऐसे में उनका शरीर मौसम में बदलाव के प्रति सेंसिटिव हो जाता है। कभी ठंडा और गर्म मौसम का असर बॉडी टेंपरेचर पर पड़ता है। इस वजह से वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बॉडी रिएक्ट करती है जिस कारण सर्दी-जुकाम या बुखार आने लगता है।

बच्चों को सर्दी-जुकाम से ऐसे बचाएं

खानपान का खास ध्यान- इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में खानपान का बड़ा रोल है। बच्चे को विटामिन सी वाले फल और सब्जियां खिलाएं। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें वायरल इंफेक्शन समेत कई हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचाता है। आयुर्वेद एक्सपर्ट किरण गुप्ता कहती हैं कि जाती ठंड में बच्चे को संतरा खिलाना चाहते हैं तो इसके लिए दोपहर का समय चुनें। बदलते मौसम में भी दही भी खिला सकते हैं क्योंकि इससे गुड बैक्टीरिया बढ़ता है जिसका फायदा इम्यूनिटी को मिलता है।

बच्चे को रोजाना हल्दी वाला दूध पिलाएं

हल्दी में करक्यूमिन होता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इस गोल्डन मिल्क को अगर बच्चा रात में पीता है तो इससे नींद भी बेहतर आती है। शरीर में सूजन है तो ये इसके कम करता है क्योंकि हल्दी में एंटीइंफ्लामेटरी गुण होते हैं। हल्दी वाला दूध गले की खराश, खांसी और ठंड में भी बहुत असरदार होता है।

मौसमी फल खिलाएं

फलों को काटकर खिलाने से बच्चे के शरीर में विटामिन सी समेत कई पोषक तत्व मिलते हैं। इतना ही नहीं फलों में फाइबर होता जो पेट की हेल्थ को दुरुस्त बनाने में मदद करता है

अंडा और दालों का सेवन

बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए उन्हें रोजाना अंडा खिलाएं। क्योंकि अंडे में प्रोटीन समेत कई दूसरे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा दालों का सूप बनाकर पिलाएं क्योंकि इनसे भी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं।

काली मिर्च और शहद

ये दोनों देसी चीजें हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि काली मिर्च में विटामिन सी काफी ज्यादा होता है। वहीं शहद में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। रात में सोने से पहले बच्चे को कुटी हुई मिर्च शहद में मिलाकर दें। रोजाना ऐसा करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है।

काढ़ा बनाकर पिलाएं

बच्चे या बड़ा, हर किसी को जाते मौसम में रोजाना आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। दालचीनी, मेथी दाना, धनिया और दूसरे गर्म मसालों का पानी बनाकर पीना चाहिए। ये इम्यून सिस्टम को नेचुरली स्ट्रांग बनाने का बेस्ट तरीका है।

क्या हैं किरायदारों के हक ? हर किसी के लिए जानना जरूरी

अगर आप भी किराए पर रहते हैं तो ये लेख आपके काम का है। यहां हम आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे।

भारत में लाखों लोग किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन अधिकतर किरायदार अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होते हैं। कई बार मकान मालिक मनमानी शर्तें थोप देते हैं, अचानक घर खाली करने को कहते हैं या बिना सूचना किराया बढ़ा देते हैं। ऐसे में किरायदारों के लिए अपने हक जानना बेहद जरूरी हो जाता है।

अगर आप नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से किराए के मकान में रहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि किन हालात में मकान मालिक आपको निकाल सकता है और किन में नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का कानून किरायदारों को भी उतनी ही सुरक्षा देता है, जितनी मकान मालिकों को। बहुत से लोग इस अधिकारों से अनजान हैं, इसी के चलते इस लेख में हम आपको किरायदारों के अहम अधिकार आसान भाषा में बता रहे हैं।

रेंट एग्रीमेंट का अधिकार

किरायदार और मकान मालिक के बीच लिखित रेंट एग्रीमेंट होना कानूनी रूप से बेहद जरूरी है।

इसमें किराया, अवधि, नियम-शर्तें, डिपॉजिट और नोटिस पीरियड साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने से भविष्य में विवाद की स्थिति में किरायदार को कानूनी सुरक्षा मिलती है।

नोटिस पीरियड

मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के किरायदार को घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

आमतौर पर 1 से 3 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है, जैसा कि रेंट एग्रीमेंट में तय होता है।

नोटिस पीरियड के बिना घर खाली कराना गैरकानूनी माना जाता है।

डिपॉजिट की वापसी

अगर किरायदार मकान को बिना किसी नुकसान के खाली करता है, तो मकान मालिक को पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटानी होती है।

केवल वैध कारणों और लिखित खर्चों के आधार पर ही कटौती की जा सकती है।

प्राइवेसी का अधिकार

किरायदार की अनुमति के बिना मकान मालिक घर में प्रवेश नहीं कर सकता।

ये किरायदार की निजता का उल्लंघन माना जाता है और कानून इसके खिलाफ सुरक्षा देता है।

मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकते

मकान मालिक किराया अचानक या मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकता।

किराया बढ़ोतरी वही मान्य होती है जो रेंट एग्रीमेंट में लिखी गई हो।

बुनियादी सुविधाएं

पानी, बिजली, सीवरेज और जरूरी मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाएं देना मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है।

इन्हें जानबूझकर बंद करना अवैध है, और ऐसे समय में किरायदार पुलिस की मदद ले सकता है।

नौकरी बदलने पर बदल गया है सैलरी अकाउंट? तुरंत करें ये काम, वरना अटक जाएगा पीएफ का पैसा

नई दिल्ली, एजेंसी। नौकरी बदलने के साथ ही अक्सर कर्मचारी अपना सैलरी अकाउंट भी बदल लेते हैं। कभी नई कंपनी के नियमों के चलते, तो कभी बेहतर बैंकिंग सुविधाओं और कम शुल्क की चाहत में नया खाता खुलवा लिया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लोग एक सबसे अहम बात भूल जाते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्वक्कस्नह्व) पीएफ का पैसा हमेशा उसी बैंक खाते में भेजता है, जो आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (रह्व) से जुड़ा होता है। अगर आपका पुराना खाता बंद या निष्क्रिय हो चुका है, तो पीएफ निकासी के समय आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अक्सर कर्मचारियों को इस परेशानी का पता तब चलता है, जब उन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है और वे क्लेम के लिए आवेदन करते हैं।

बदलाव से पहले पोर्टल पर इन बातों की कर लें जांच

बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने से पहले ईपीएफओ के मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर लॉग इन करके यह जांचना जरूरी है कि वर्तमान में आपका यूएएन किस बैंक खाते से जुड़ा है। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि नौकरी बदलने पर बैंक डिटेल अपने आप अपडेट हो जाती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपका आधार और पैन कार्ड पूरी तरह से सत्यापित (वेरिफाई) हो। यदि आपके नाम या अन्य जानकारी में स्पेलिंग की छोटी सी भी गलती है और वह मैच नहीं कर रही है, तो आपका अपडेट रिक्वेस्ट सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए, अगर कोई भी जानकारी मेल नहीं खाती है, तो सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले उसे ठीक करवाएं।

ईपीएफओ में ऐसे अपडेट करें अपना नया बैंक अकाउंट

पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद 'मैनेज' सेक्शन में जाएं और 'केवाईसी' विकल्प पर क्लिक करें। वहां आपको अपना मौजूदा बैंक खाता दिखाई देगा। इसके बाद अपना नया बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी (ङ्कस्नस्ष्ट) कोड बहुत ध्यान से दर्ज करें, क्योंकि आमतौर पर सबसे ज्यादा गलतियां नंबर फीड करते समय ही होती हैं। जरूरत पड़ने पर एक कैंसल किए गए चेक की साफ तस्वीर भी अपलोड करें। डिटेल सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सीधे पास नहीं होती, बल्कि यह अप्रूवल (मंजूरी) के लिए आपकी मौजूदा कंपनी के पास जाती है। यदि आपकी कंपनी का एचआर विभाग इसे मंजूर नहीं करता है, तो खाते में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट पेंडिंग होने पर अनिश्चित काल तक इंतजार करने के बजाय अपनी कंपनी के सैलरी या एचआर विभाग से तुरंत संपर्क करें।

भविष्य की परेशानी से बचने के लिए समय रहते करें यह काम

अगर आप पीएफ निकालने का क्लेम करते हैं और आपकी बैंक डिटेल गलत पाई जाती हैं, तो ईपीएफओ पेमेंट को प्रोसेस नहीं करेगा। आपका क्लेम खारिज हो जाएगा और आपको पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी। नौकरी छोड़ने के बाद या किसी आपात स्थिति में पीएफ एडवांस निकालते समय पैसों का अटकना बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि पूरे करियर के दौरान आपका यूएएन नंबर एक ही रहता है और इसके तहत एक समय में केवल एक ही बैंक खाता सक्रिय रह सकता है। इसलिए जब भी आपका सैलरी अकाउंट बदले, ईपीएफओ पोर्टल पर इसे अपडेट करना अपनी प्राथमिकता में शामिल करें। पांच मिनट का यह छोटा सा काम आपको भविष्य में हफ्तों की परेशानी से बचा सकता है।

'पीएम मोदी हमारा फायदा उठा रहे थे', टैरिफ पर झटके के बाद व्यापार समझौते को लेकर बोले ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति के नए फैसले के बाद भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर लगने वाला टैरिफ घटाकर 10% कर दिया गया है, जो पहले 18% तय किया गया था। यह नया अस्थायी टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और फिलहाल 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा। ट्रंप ने इसे 'अस्थायी आयात शुल्क' बताया है, जिसका मकसद अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करना है।

'पीएम मोदी हमारा फायदा उठा रहे थे'

वहीं, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा कि पीएम मोदी हमारा फायदा उठा रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले के बावजूद भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप के मुताबिक, 'कुछ भी नहीं बदला है- भारत हमें टैरिफ देता रहेगा, जबकि अमेरिका भारत को कोई टैरिफ नहीं देगा।'

पहले व्यवस्था उलटी थी- डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पहले व्यवस्था उलटी थी और भारत अमेरिका पर ज्यादा फायदा उठा रहा था, लेकिन उनकी सरकार ने समझौता पलटकर इसे 'फेयर डील' बना दिया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें 'महान व्यक्ति' बताया, लेकिन कहा कि व्यापार के मामले में भारत पहले अमेरिका से ज्यादा स्मार्ट साबित हुआ था।

ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ठहराया अवैध

यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की तरफ से पहले लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहरा दिया। अदालत ने 6-3 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी कानूनी सीमा से बाहर जाकर इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा दिए थे। यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

भारत पर ट्रंप ने लगाया था 25% टैरिफ

इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा बना था, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगे 25% दंडात्मक टैरिफ हटाकर उन्हें 18% तक कम कर दिया था। ये दंडात्मक टैरिफ भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए थे। ट्रंप ने कहा था कि भारत ने उनके कहने पर रूस से ऊर्जा आयात काफी कम किया और अमेरिकी ऊर्जा खरीदने की प्रतिबद्धता जताई।

अब भारत पर लगेगा 10% टैरिफ

अब नए फैसले के तहत पूरी दुनिया के देशों पर समान रूप से 10% का अस्थायी आयात शुल्क लगाया जा रहा है, इसलिए भारत पर अलग से 18% वाला टैरिफ लागू नहीं रहेगा। हालांकि कुछ जरूरी सामान जैसे दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा उत्पाद, कृषि वस्तुएं, वाहन और कुछ खनिज इस नए टैरिफ से बाहर रखे गए हैं ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो।

फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों पर बरसे ट्रंप

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने जजों की कड़ी आलोचना की और कहा कि उनका निर्णय निराशाजनक है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत के साथ व्यापार समझौता जारी रहेगा और भारत को अब भी अमेरिका को टैरिफ देना होगा, जबकि अमेरिका भारत को टैरिफ नहीं देगा। ट्रंप ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्ते को 'बहुत शानदार' बताया।

बड़े कारोबारी रहे चुप, लेकिन एक खिलौना कारोबारी ने ट्रंप से लिया लोहा

भारतवंशी नील कात्याल कौन? : जिन्होंने पलट दिया ट्रंप टैरिफ का पूरा खेल, बने ऐतिहासिक फैसले का चेहरा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर राजनीतिक बयानबाजी तेज थी और बड़े कॉरपोरेट घराने खामोश थे, तब एक खिलौना कारोबारी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह कहानी किसी बड़े उद्योगपति की नहीं, बल्कि एक पारिवारिक कंपनी चलाने वाले सीईओ की है, जिसने माना कि नीति गलत है तो उसका विरोध होगा। फिर वो लड़ाई चाहे देश की सरकार या फिर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ही क्यो न हो। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि रिक वोल्डेनबर्ग है।

वोल्डेनबर्ग का कहना था कि यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि पीढ़ियों से खड़े किए गए कारोबार के अस्तित्व की लड़ाई थी। रिक वोल्डेनबर्ग शिकागो के पास स्थित शैक्षणिक खिलौना कंपनी लर्निंग रिसोर्सेज के सीईओ हैं। उनकी कंपनी की स्थापना उनकी मां ने की थी। 'लिबरेशन डे' टैरिफ की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने वकीलों से संपर्क किया और राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती दी। उनका आरोप था कि आईईईपीए कानून के तहत लगाए गए टैरिफ छोटे और मध्यम उद्योगों पर भारी बोझ डाल रहे हैं, जबकि बड़ी कंपनियां लॉबिंग और संसाधनों के दम पर खुद को बचा लेती हैं।

वोल्डेनबर्ग ने क्यों लड़ी ये लड़ाई?

कंपनी के ज्यादातर शैक्षणिक खिलौने एशिया में बनते हैं, इसलिए टैरिफ बढ़ते ही लागत अचानक बढ़ गई।

बढ़े हुए आयात शुल्क के कारण मुनाफा घटने लगा और व्यापार पर सीधा असर पड़ा।

नए वेयरहाउस का प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ा। मार्केटिंग बजट में कटौती करनी पड़ी।

नई भर्तियां रोक दी गईं और विस्तार की योजनाएं ठप हो गईं।

वोल्डेनबर्ग को पहले ही अंदेशा था कि आय घटेगी और कंपनी सिमटेगी, और बाद में यही हुआ भी।

एक खिलौने से भड़की चिंगारी

कंपनी का लोकप्रिय उत्पाद 'बबल प्लश योगा बॉल बडीज' इस विवाद का प्रतीक बन गया। पहले चीन में उत्पादन हुआ, फिर भारत में शिफ्ट किया गया। उसके बाद अचानक नए टैरिफ लागू हो गए। एक शिपमेंट पर कंपनी को लगभग 50,000 डॉलर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा। वोल्डेनबर्ग ने कहा कि उत्पादन को बार-बार देशों में बदलना पड़ा, जैसे कंपनी भटकती फिर रही हो। इस कानूनी लड़ाई में बड़े अमेरिकी कॉरपोरेट आगे नहीं आए। जानकारों का कहना है कि बड़ी कंपनियों के पास नकदी भंडार और सप्लाई चेन प्रबंधन की क्षमता होती है। वे अदालत के बजाय लॉबिंग का रास्ता अपनाती हैं। इसके उलट, दर्जनों छोटे कारोबारियों और कुछ गैर-लाभकारी संगठनों ने वोल्डेनबर्ग का समर्थन किया। और कोर्ट में ही लड़ाई लड़ी।

सुप्रीम कोर्ट में क्या था दांव?

वोल्डेनबर्ग और अन्य कंपनियों ने दलील दी कि 1977 का आईईईपीए कानून राष्ट्रपति को व्यापक टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। कई निचली अदालतों ने भी माना कि टैरिफ कानूनी सीमा से बाहर थे। इस मामले में अरबों डॉलर के व्यापार और संभावित 100 अरब डॉलर से अधिक रिफंड का सवाल जुड़ा था। फैसला सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे कारोबारी तंत्र के लिए अहम माना गया।

इस लड़ाई में कितने डॉलर हुए खर्च?

रिक वोल्डेनबर्ग ने स्वीकार किया कि उनकी कानूनी फीस लाखों डॉलर तक पहुंच गई है। उन्होंने इसे जरूरी निवेश बताया। उनका कहना है कि अमेरिका के लाखों छोटे व्यवसाय इसी तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग सीधे राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती देने का जोखिम उठाते हैं। इसी वजह से वोल्डेनबर्ग का नाम इस लड़ाई में अलग पहचान बना सका।

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार देकर बड़ा फैसला सुनाया। इस ऐतिहासिक फैसले के केंद्र में एक भारतीय मूल का नाम उभरा, नील कात्याल। नील ने ही अदालत में ट्रंप के उस कदम को चुनौती दी, जिसमें 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईईईपीए का इस्तेमाल कर लगभग सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर टैरिफ लगाए गए थे। नील कात्याल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि राष्ट्रपति ने आपात आर्थिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि टैरिफ दरअसल टैक्स होते हैं और टैक्स लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस को है, न कि राष्ट्रपति को। कात्याल ने इन टैरिफ को अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक टैक्स बताया। सुप्रीम कोर्ट ने छह-तीन के बहुमत से कहा कि संविधान के तहत टैक्स लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है।

यह मामला छोटे अमेरिकी कारोबारियों द्वारा दायर किया गया था, जिन्हें लगा कि टैरिफ से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक दबाव का जरूरी कदम बताया था। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि आपात शक्तियों के नाम पर राष्ट्रपति व्यापक टैक्स नहीं लगा सकते। नील कात्याल का जन्म शिकागो में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर हुआ। उनके पिता इंजीनियर और माता डॉक्टर थीं। उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से पढ़ाई की। वह अमेरिका के कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में 50 से अधिक मामलों में पैरवी कर चुके हैं।

एआई समिट में यूथ कांग्रेस का विरोध, आज 4 वर्कर्स की पेशी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार 20 फरवरी को ट्रेड डील के खिलाफ विरोध जताया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के गंभीर प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई। इसमें क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, पब्लिक सर्वेंट को चोट पहुंचाना, पब्लिक सर्वेंट पर हमला करना और ड्यूटी करने में रुकावट डालना, पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना और कॉमन इंटेंशन शामिल हैं। फिलहाल, कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बचाव पक्ष ने कहा यह सभी पीस फूल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इन लोगों का राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी एक राजनैतिक दल से जुड़ा है जो विपक्ष में है। भारत मंडपम मे प्रदर्शन में शामिल हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया कहीं भी कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने किसी को चोट पहुंचाई। प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में पुलिस रिमांड की कोई जरूरत नहीं है।

पुलिस को धक्का देने की कोशिश

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्हें धक्का दिया गया, जिससे उन्हें चोट लगी है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि इनके मोबाइल जब्त हैं ये अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वहां जाकर जांच करनी है और साजिश का पता लगाना है कि इस तरह की टी शर्ट कहां छापी गई। ये सब नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट से मिलता-जुलता था।

एंटी नेशनल नारे लगाने का आरोप

दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये सभी एंटी नेशनल स्लोगन नारा लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा आरोपियों ने देश को बांटने वाले नारे लगाए। पुलिस ने यह कार्रवाई तब की जब प्रदर्शनकारियों के एक ग्रुप ने एग्जीबिशन हॉल नंबर 5 में मार्च किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली सफेद टी-शर्ट पहनी हुई थी। कुछ ने इस तरह की टी-शर्ट को पकड़ रखा था। साथ ही इंडिया-US ट्रेड डील,एपस्टीन फाइल्स और प्रधानमंत्री इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे भी लिखे थे। इस वजह से ये हंगामा जल्द बढ़ गया। पुलिस ने कहा कि वे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी कॉन्सपिरेसी एंगल की जांच कर रहे हैं। ACP (नई दिल्ली) देवेश महला ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। FIR में कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

एआई समिट में हंगामे के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने AI समिट में टी शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा भी सड़क पर उतर आया। युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और अन्य नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। वीरेन्द्र सचदेवा को हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 163 लगने का हवाला देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटा रही है। बीजेपी का प्रदर्शन खत्म हो गया है।

भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि देश का विश्व पटल पर अपमान करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस देश से माफी मांगें। बीजेपी युवा मोर्चा ने साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

'कांग्रेस के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है'

इस प्रोटेस्ट में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश का गद्दार है। जनता ने उनकी वहीं पिटाई कर दी थी। ये कांग्रेस के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। दिल्ली और देश की जनता माफ नहीं करेगी। मनोज तिवारी ने कहा कि AI समिट में 80 से ज्यादा देशों के लोग आए हैं और भारत की सराहना की। ये भारत का AI इंपैक्ट समिट था। भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ हुई। उन्होंने कहा कि हम आगे जाकर दुर्घटनाओं को कैसे कम करेंगे ये भी इसमें बताया गया। उन्होंने कहा कि हर साल 5 लाख रोड एक्सिडेंट होते हैं। 2.5 लाख लोग मरते हैं। हम एक्सीडेंट की संख्या को 4 लाख तक लाए। अगर ड्राइवर हो जाए तो ये सजग करेगा। ऐसा इनको पच नहीं रहा है। भारत बम गोलों से नहीं हारेगा। इसलिए वैचारिक आतंकवादी सक्रिय हैं।

'राहुल गांधी का खून इटली का है'

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कल की घटना कोई मामूली घटना नहीं है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम है। किराए के कुछ गुंडे कांग्रेस ने समिट में भेजे। एक गरीब चाय वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया ये बात उनको पच नहीं रहा है। मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे उनको पता ही नहीं चला। ये समिट देश की तरक्की को बताता है। भारत विश्व गुरु बनने वाला है ये बताता है। राहुल गांधी का खून इटली का है। उन्होंने कहा कि AI समिट राष्ट्र का प्रतीक है।

नेल्सन मंडेला से की प्रियंका चोपड़ा की तुलना, विन डीजल ने देसी गर्ल को सराहा, बोले– मैं आपको सीक्रेट...

प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' जल्द ही रिलीज होने वाली है। देसी गर्ल इस फिल्म के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं। लॉस एंजेल्स में भी इस फिल्म का प्रीमियर हुआ। जिसमें हॉलीवुड एक्टर विन डीजल भी शामिल हुए। प्रीमियर पर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को लेकर काफी कुछ कहा।

फिल्म 'द ब्लफ' के लॉस एंजेल्स प्रीमियर में विन डीजल ने प्रियंका के नेचर को लेकर एक राज खोल दिया। वह कहते हैं, 'मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताने जा रहा हूं। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में बहुत कमाल की हैं। उनमें जबरदस्त टैलेंट है। एक स्क्रीनिंग के दौरान यूरोप में उन्होंने मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। हम दोनों एक ही दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ स्वर्गीय नेल्सन मंडेला के बारे में सोचें। इंटरनेशनल एक्टिविस्ट नेल्सन मंडेला, प्रियंका चोपड़ा और मैं, हम सब इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।'

कब रिलीज होगी फिल्म 'द ब्लफ'?

प्रियंका चोपड़ा और कार्ल अर्बन स्टारर 'द ब्लफ' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। यह 25 फरवरी 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है। फ्रैंक ई फ्लावर्स के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक कैरिबियन महिला की कहानी है, जिसका सीक्रेट पास्ट तब सामने आता है जब समुद्री लुटेरे उसके आइलैंड पर हमला करते हैं। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने गजब का एक्शन भी किया है।

प्रियंका चोपड़ा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं?

प्रियंका चोपड़ा के करियर फ्रंट की बात करें तो वह हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' और राजामौली की पैन इंडिया फिल्म 'वाराणसी' का हिस्सा हैं। 'वाराणसी' फिल्म में प्रियंका चोपड़ा साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म बड़े स्तर पर बन रही है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए प्रियंका चोपड़ा लगातार भारत आ रही हैं। अब उनका नाम फिल्म '007 बॉन्ड' सीरीज को लेकर भी सामने आ रहा है।

इस बार परिणीति नहीं, इस हीरोइन को अपनी बायोपिक में देखना चाहती हैं साइना नेहवाल? कहा- 'बहुत प्यारी लड़की है'

साइना नेहवाल की साल 2021 में बायोपिक रिलीज हुई। इसमें परिणीति चोपड़ा ने लीड रोल अदा किया। अगर, बैडमिंटन स्टार की बायोपिक दोबारा बनती है तो वे किसे अपने रोल में देखना पसंद करेंगी? उन्होंने इसका जवाब दिया है।

भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर आधारित फिल्म 'साइना' साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने साइना का लीड रोल अदा किया। हालांकि, अपनी बायोपिक में साइना जिस एक्ट्रेस को लीड रोल में देखना चाहती हैं, वह हैं श्रद्धा कपूर। आज भी श्रद्धा ही अपनी बायोपिक के लिए साइना की पहली पसंद हैं।

आज भी श्रद्धा कपूर पहली पसंद

बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने हाल ही में यह कहा कि अगर उनकी बायोपिक फिर से बनती है तो श्रद्धा कपूर उनकी पहली पसंद हैं। साथ ही साइना ने परिणीति के साथ अपने रिश्ते पर भी बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही उस चर्चा पर भी बात की, जिसमें कहा जा रहा है कि परिणीति ने कथित तौर पर साइना को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है।

बायोपिक के लिए पहले भी श्रद्धा को चुना गया था

साइना नेहवाल ने कहा है कि अगर उनकी बायोपिक दोबारा बनती है, तो भी वह स्क्रीन पर अपने किरदार के लिए एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को ही चुनेंगी। साइना ने यह बात तब कही है, जब ऐसी चर्चा है कि परिणीति ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिणीति ने साल 2021 में साइना का रोल अदा किया। मगर, साइना नेहवाल ने असल में श्रद्धा को ही चुना था। मगर, आखिर में बात नहीं बन पाई।

श्रद्धा कपूर से अब भी होती है बात

हाल ही में विक्की लालवानी के साथ एक बातचीत में साइना से पूछा गया कि अगर बायोपिक दोबारा बनती है तो वह अपने रोल के लिए किसे कास्ट करना चाहेंगी? इस पर उन्होंने तुरंत श्रद्धा का नाम लिया। शुरू में इस रोल के लिए श्रद्धा को कास्ट किया गया था, लेकिन खबर है कि शूटिंग शुरू होने से पहले हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें हटना पड़ा। साइना ने जोर देकर कहा कि एक्ट्रेस श्रद्धा हमेशा इस रोल के लिए उनकी पहली पसंद थीं। उन्होंने कहा, 'हम अभी भी टच में हैं और मैं उनसे कई बार मिल चुकी हूं। वह बहुत प्यारी लड़की हैं। वह फिल्म करने के लिए मान गई थीं, लेकिन डेंगू की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा'।

परिणीति के लिए क्या कहा?

परिणीति के साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए साइना ने कहा कि उनकी बातचीत ज्यादातर प्रोफेशनल थी। उन्होंने बताया, 'दोस्ती के लिए साथ में बहुत समय बिताना पड़ता है, लेकिन फिल्म को जल्दी रिलीज करना था, इसलिए ज्यादा समय नहीं मिल पाया। हम रोज नहीं मिलते थे'। साइना ने आगे कहा कि परिणीति ने रोल की तैयारी में काफी मेहनत की। बैडमिंटन की टेक्निकल बातें सीखीं। बता दें कि फिल्म 'साइना' ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com